खण्ड-07 सत्र-04 / अंक-38

मंगलवार 21 मार्च, 2023 / 30 फाल्गुन, 1944 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

सातवीं विधान सभा

चौथा सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-07 सत्र-04 में अंक 36 से अंक 43 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

राज कुमार

सचिव

RAJ KUMAR

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप-सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-4 मंगलवार, 21 मार्च, 2023/30 फाल्गुन, 1944 (शक) अंक-38

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	सदन में अव्यवस्था	3-11
3.	बजट के संबंध में वित्त मंत्री का वक्तव्य	12-14
4.	सदन में अव्यवस्था	15-29
5.	माननीय सदस्य श्री विजेन्द्र गुप्ता को एक वर्ष तक हाउस से बाहर रखने के संबंध में प्रस्ताव	30-32
6.	केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार का बजट रोके जाने के संबंध में माननीय सदस्य श्री संजीव झा का संकल्प एवं उस पर चर्चा	33-88

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-4 मंगलवार, 21 मार्च, 2023/30 फाल्गुन, 1944 (शक) अंक-38

दिल्ली विधान सभा

सदन पूर्वाह्न 11.07 बजे समवेत हुआ।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

1 श्री अजेश यादव
2 श्री अखिलेशपति त्रिपाठी
3 श्रीमती ए. धनवंती चंदीला ए.
4. श्री अजय दत्त
5. श्री अमानतुल्ला खान
6. श्री अब्दुल रहमान
7. श्रीमती बंदना कुमारी
8. सपुरी भावना गौड़
9. श्री बी एस जून
10. श्री धर्मपाल लाकड़ा
11. श्री दुर्गेश कुमार
12. श्री गिरीश सोनी
13. श्री गुलाब सिंह
14. श्री हाजी युनूस
15. श्री जय भगवान
16. श्री जरनैल सिंह
17. श्री कुलदीप कुमार
18. श्री महेंद्र गोयल

19. श्री मुकेश अहलावत
20. श्री नरेश यादव
21. श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर
22. श्री प्रलाद सिंह साहनी
23. श्री प्रवीण कुमार
24. श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस
25. श्री प्रकाश जारवाल
26. श्री ऋतुराज गोविंद
27. श्री राजेश गुप्ता
28. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
29. श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों
30. श्री राजेश ऋषि
31. श्री रोहित कुमार
32. श्री शरद कुमार चौहान
33. श्री संजीव झा
34. श्री सोमदत्त
35. श्री शिवचरण गोयल
36. श्री सोमनाथ भारती
37. श्री सही राम
38. श्री एस के बग्गा
39. श्री विनय मिश्रा
40. श्री वीरेंद्र सिंह कादियान
41. श्री अभय वर्मा
42. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
43. श्री अजय कुमार महावर
44. श्री जितेंद्र महाजन
45. श्री मदन लाल
46. श्री मोहन सिंह बिष्ट
47. श्री ओमप्रकाश शर्मा
48. श्री पवन शर्मा
49. श्री रघुविंदर शौकीन
50. श्री शोएब इकबाल
51. श्री सुरेंद्र कुमार
52. श्री विजेंद्र गुप्ता
53. श्री विशेष रवि

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-4	मंगलवार, 21 मार्च, 2023/30 फाल्गुन, 1944 (शक)	अंक-38

दिल्ली विधान सभा

सदन पूर्वाह्न 11.07 बजे समवेत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए ।

राष्ट्रगीत-वन्दे मातरम्

माननीय अध्यक्षः आज की बैठक में सभी माननीय सदस्यों का स्वागत है। यह मेरे संज्ञान में आया है कि आज वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली का वार्षिक बजट पेश नहीं हो पायेगा। इस विधान सभा में पूरे देश के विधान मंडलीय इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह सत्र बजट को प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था और बजट ही पेश नहीं हो पा रहा है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, असंवैधनिक और असाधारण घटना है। मैं चाहूँगा कि श्री कैलाश गहलौत जी, माननीय वित्त मंत्री इस संबंध में वक्तव्य दें।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी मैंने कुछ रूलिंग दिया है पहले उसको तो डिसाइड करिये।

माननीय अध्यक्षः किसको।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी

...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्षः आप बैठ जाइये। बजट भी लीक कर दिया। आप बैठ जाइये नीचे।

...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्षः कौन-सा नोटिस दिया। उससे पहले। बैठ जाइये। बैठ जाइये नीचे। नहीं ये गलत चीज है। ये गलत चीज है बिल्कुल। बहुत गलत चीज है ये। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ विजेन्द्र जी आप बैठ जाइये। मैंने पढ़ लिया है। मैंने पढ़ लिया है। मैंने पढ़ लिया है इसको। पहले वित्त मंत्री जी को भाषण देने दीजिए।...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्षः आपने जो लैटर लगा के दिया है उसके ऊपर वो लैटर मैंने पढ़ लिया है सारा इसके बाद मेरे चेम्बर में बात करिये। लेटर का जवाब लेटर से दिया जाएगा ना। लेटर का जवाब लेटर से देंगे। आपने नियम लिखा है उसमें कोई मैं जवाब दूँगा आपको। मैं जवाब दूँगा आपको। अभी वित्तमंत्री जी को बोलने दें। आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए बोल रहे हैं केवल, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। बैठ जाइये नीचे। परेशान किया हुआ है दिल्ली की जनता को। दुखी है दिल्ली की जनता तुम लोगों से।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप रूलिंग दीजिए।

माननीय वित्त मंत्री (श्री कैलाश गहलोत): अध्यक्ष जी मेरे ख्याल से।

माननीय अध्यक्षः मैं वार्निंग दे रहा हूँ। मैं विजेन्द्र जी आखरी वार्निंग दे रहा हूँ आपको। बैठ जाइये आराम। एक तो लैंगुएज उसकी बहुत गलत है। मैंने देख लिया पढ़ लिया वो सारा। पढ़ लिया मैंने।

...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्षः आज बजट के लिए है केवल ये। आज ये बजट के लिए है केवल। आप बाद में बात रखियेगा।

आप बैठिये, आप बैठिये। आप बैठिये पहले। आप बैठिये मैं अभी वित्त मंत्री जी मैं वित्त मंत्री जी को बोलने दीजिये उसके बाद सुनूँगा, वित्त मंत्री जी को बोलने दीजिये उसके बाद सुनूँगा। पहले वित्त मंत्री बोलेंगे।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं वित्त मंत्री जी को बोलने दीजिये। उसके बाद बात करूंगा। उसमें लेटर में कोई नियम नहीं है मैंने मंगवा लिया। किस नियम में नोटिस दिया है आपने?

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः कौन से नियम में नोटिस दिया है, कोई नियम तो होगा विधान सभा का?

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चिल्लाईये मत। चिल्लाईये मत।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चिल्लाईये मत।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आपने नोटिस दिया कहीं लिखा है इसपर? कोई रूलिंग लिखी है इस पे? किस रूलिंग में दिया है? ये लेटर आया है मैं लेटर का जवाब दूँगा आपको। मैं लेटर का प्रॉपर जवाब दूँगा। कोई रूलिंग नहीं लिखा है इस पे। उठाया लेटर लिख के डाल दिया।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः पढ़ लिया मैंने सारा।

...व्यवधान...

श्री विजेंद्र गुप्ताः अंडर रूल 56 सबसे उपर टॉप पर।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अगर रूल्स के मुताबिक कोई नोटिस दिया है, ये एक वरिष्ठ विधायक हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः देखिये अब आखिरी लाईनये पढ़िये आउटकम बजट का आपने लिखा है। आपने आउटकम बजट लिखा है। आपने आउटकम बजट लिखा है। मैं इस पर बाद में रूलिंग दूँगा। मैं अपनी रूलिंग दूँगा। मैं आपको रूलिंग दूँगा बाद में इस पर, बैठ जाईये अभी। अभी वित्त मंत्री को बोलने दीजिये मैं रूलिंग दूँगा इस पर अभी बाद में, वित मंत्री के बोलने के बाद।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः हां अभी मैं इसके बाद दूँगा आपको, इसकी रूलिंग दूँगा पूरी। देखिये मैंने सुन लिया है..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं विजेंद्र गुप्ता जी ने जो कुछ इसमें लिखा है।

श्री विजेंद्र गुप्ताः मैंने चर्चा के लिए...

माननीय अध्यक्षः मैंने पढ़ लिया है। और मैं इसको अभी पहले वित्त मंत्री जी बोलेंगे मैं उसके बाद रूलिंग दूँगा। वित्त मंत्री जी बोलेंगे उसके बाद रूलिंग दूँगा। मैंने पहले बोला वित्त मंत्री जी बोलेंगे उसके बाद रूलिंग दूँगा ।

श्री ओम प्रकाश शर्माः रूलिंग तो आपको पहले देनी चाहिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य बैठेंगे। मैं पढ़के सुना रहा हूँ ruling बैठिये। हां इसके पेज नंबर पे आपके पास बुक है सुन लीजिये।

श्री विजेंद्र गुप्ताः आप जवाब दीजिये न पहले।

माननीय अध्यक्षः आप, मैं ये पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। आप बैठिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आप बैठ जाईये। आप बैठेंगे तब पढ़ के सुनाउंगा। पहले बैठिये। पहले बैठिये नीचे। पहले नीचे बैठिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः पहले मैं आग्रह कर रहा हूँ नीचे बैठिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चिल्लाईये मत। पहले नीचे बैठिये। हां वो मैंने इजाजत दी है उनको खड़ा होने की। question involving a Breach of Privilege or Contempt either of a member or of the House of a Committee thereof may with the consent of the Speaker, there is no consent of the Speaker.

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं कंसेंट नहीं दे रहा हूँ इस पर I am not giving the consent मैं कंसेंट नहीं दे रहा हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः क्यों नहीं देंगे

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं दे रहा हूँ मैं consent.

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं दे रहा हूँ मैं कंसेंट ये मेरी मर्जी है। मेरी तानाशाही है ये। ये मेरी तानाशाही है, मैं नहीं दे रहा हूँ कंसेंट।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बैठिए। आपको पढ़ के सुना दिया, फिर आप बदतमीजी पर उतरे।

माननीय वित्त मंत्रीः अध्यक्ष जी, मेरे ख्याल से पहली बार पूरे देश में हुआ है कि एक चुनी हुई सरकार को अपना बजट पेश नहीं करने दिया जा रहा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आप लोग बैठिए, मैं कर रहा हूँ ये मेरा काम है मैं व्यवस्था करूंगा। आप लोग बैठिए? ये मेरा काम है आपका काम नहीं है। आप बैठ जाईये?

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी मैंने सब कुछ देख लिया है। मैं अभी बात करूंगा इस पर, आपने कहा था न इस पर रूलिंग दीजिए, मैं अभी वित्त मंत्री जी को बोलने दीजिए उसके बाद बात करूंगा आपसे। पहले आप छोड़ दीजिए। मार्शल्स विजेन्द्र को निकालिए बाहर। विजेन्द्र जी को बाहर करिये?

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं बिल्कुल नहीं। मैं अभी सुनाऊंगा इसको।

...व्यवधान...

श्री ओम प्रकाश शर्माः ये गलत है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः हां मैं गलत कर रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ बिल्कुल। मैं मान रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। यहां दिल्ली की जनता को फांसी पर लटका रहे हो, वो आप को गलत नहीं दिखाई देता। आज बजट का दिन था बजट पेश नहीं हो रहा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः जाईये, मेरे से बात करियेगा मैं बात करूंगा। बात करियेगा मेरे से अभी लूँगा इसको। शोर मचाने से।

...व्यवधान...

माननीय वित्त मंत्रीः अध्यक्ष जी मेरे ख्याल से

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई मैं कुछ नहीं सुन रहा हूँ। आपको बाहर जाना है जाईये सब।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आपने पढ़ा है ये नोटिस, नोटिस पढ़ा है ये?

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आप बैठिए, पूछना चाहिए बजट सैशन...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आपसे पूछ के आयेंगे, आपसे पूछ के आयेंगे, बजट नहीं मिला। आपसे पूछ के आयेंगे। गुंडागर्दी पर उतरे हुए हो। सारी बीजेपी गुंडागर्दी पर उतरी हुई है, महा गुंडे बन गये हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ओमप्रकाश जी, आप चिल्लाईये मत।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आपको कानून मालूम है?

...व्यवधान...

श्री अभय वर्माः हां कानून पता है बिना...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः यार इनको समझाओ यार, कुछ मालूम नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। बिजनैस कमेटी में अप्रूवल हुआ है। आपको मालूम है कुछ भी, आप जाईये यहां से। बजट का अप्रूवल नहीं हुआ, बैठ जाईये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः करिये वाकआउट। विपक्ष को अन्याय करने के बाद अपने अन्याय की आलोचना सुनने की आदत खत्म है और इसलिए वो वाकआउट के अननेसेसरी शोर मचाया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी।

माननीय वित्त मंत्रीः अध्यक्ष जी मेरे ख्याल से पूरे देश में और मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई चुनी हुई सरकार को अपना बजट नहीं पेश करने दिया जा रहा। बड़े दुख के साथ मैं ये सदन को, बड़े दुख और भारी मन के साथ मैं ये सदन को बताना चाहता हूँ कि कल केंद्रीय सरकार ने हमारे बजट को पेश होने से रोक दिया। ये सबको पता था कि 21 तारीख को बजट पेश होना है। हमारे जो बिजनस है हाउस का उसमें लिस्टिड है। एलजी साहब को मालूम था कि 21 तारीख को बजट पेश होना है, 10 तारीख को पूरा बजट और कम्पलीट डॉक्यूमेंटस के साथ एमएचए को जो लॉ की रिक्वायरमेंट है, एमएचए को पूरा बजट भेज दिया गया। कल लगभग 2 बजे के आसपास मुझे मालूम

चला कि एमएचए ने कुछ query रेज की है। तो तुरंत मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की, जो प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उनसे बात की, की भई क्या एमएचए ने भेजा है। दो बजे से लेकर शाम के 6 बज गए। चीफ सेक्रेटरी से मैंने दो बार बात की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस से शायद हो सकता है कि तीन या चार बार बात की। की भई जो भेजा है वो आप भेजिए फटाफट ताकि उसको हम देखें। क्योंकि समय बिल्कुल नहीं था। शाम को 6 बजे जो एमएचए से लेटर आया उसके साथ वो फाइल आई, तुरंत हमने उसको देखा, जो भी उन्होंने उसमें कुछ चीजें लिखी उसका जवाब बनाया और तुरंत फिर सीएम साहब से बात किया और ठीक 9 बजे हमने उसको एलजी के पास भेज दिया। वहां से लगभग साढ़े 10 बजे के आसपास फाइल वापस लौटी। तो ये चीजें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ, इस सदन के सामने रख रहा हूँ कि अगर चुनी हुई सरकार को अपना बजट भी अगर पेश नहीं करने दिया जाएगा तो मेरी ख्याल से इससे बड़ा घोर अन्याय, इससे बड़ा कोई unconstitutional Act नहीं हो सकता। रात को ही फाइल जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के घर भेजी गई सुबह मैंने फिर बात किया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस से, तो उन्होंने बताया की जो जवाब था वो मेल के द्वारा भी और जो फिजीकल फाइल भी एमएचए को सबमिट कर दी गई है। ये मैने इस दस तारीख को जो हमने बजट भेजा था और इसमें एक चीज एक चीज मेरी समझ के बाहर है, जो लैटर लिखा गया एमएचए से वो 17 तारीख को साढ़े

पांच बजे 17 तारीख को साढ़े पांच बजे लिखा गया। सत्रह तारीख से लेकर 20 तारीख की दो बजे तक फाईनांस मिनिस्टर को ये नहीं पता है कि कोई चिट्ठी एमएचए से आई है या नहीं आईं मेरे ख्याल से इसका प्रोपर इन्वेस्टीगेशन होना चाहिए कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर जिसमें कि सरकार का बजट जो है वो पेश होना है। तो अगर ऐसी कोई चिट्ठी 17 तारीख को अगर आई है इसमें टाइम लिखा हुआ है साढे पांच मेल के द्वारा तो मेरे ख्याल से Chief Secretary is under a legal obligation कि वो तुरन्त इस तरह के इंपोर्टेंट मेल्स को फाईनांस मिनिस्टर के संज्ञान में उनको लाना चाहिए था। सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए था ताकि ये जो समय बीच में जो बर्बाद हुआ ये नहीं होता और अगर इस तरीके से बजट में भी अगर काम रोका जाएगा तो अध्यक्ष जी फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार क्यों चुनी। फिर केबिनेट किस लिए है। फिर चीफ मिनिस्टर किस लिए है। फिर दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं वो किस लिए है। दो करोड दिल्ली की जनता ने एक सरकार चुनी, एक सीएम चुना काम करने के लिए अगर हर चीज में इस तरीके से अगर वो तंग करना है उनको और अगर काम नहीं करने देना तो अध्यक्ष जी मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है। जब केबिनेट ने बजट को अप्रूव करके एलजी को भेज दिया। जब सारी चीजें as per जो legal procedure है उसके द्वारा हम चल रहे हैं तो फिर किस बात का आब्जेक्शन है। ये सरासर मेरे ख्याल से अध्यक्ष जी ये जो सरकार है उसको

काम नहीं करने देना। दिल्ली की जनता को परेशान करना। अब आप देखिए इसके consequences क्या है। अगर बजट पेश नहीं होता है तो इसका मतलब सबकी तनख्वाहें भी रूक जायेगी।

तो मेरे ख्याल से अध्यक्ष जी इससे बड़ा unconstitutional act मेरे ख्याल से नहीं हो सकता और जो फेक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं इनकी प्रापर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री संजीव झाः मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय ये बड़ा गंभीर विषय है जिस तरह से अभी माननीय मंत्री जी ने सारी बातें सदन को बताईं हम सभी सदस्य इस बात को लेकर चिंतित हैं। अगर इस तरह से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिल्ली के लोकप्रिय सरकार जिससे दिल्ली की जनता मुझे लगता है इस पर...

(सत्ता पक्ष के सभी सदस्य नारे लगाने लगे और वैल में आ गये)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ अपनी–अपनी सीट पर बैठें। माननीय सदस्य गण अपनी–अपनी सीट पर बैठें। माननीय सदस्य गण अपने–अपने स्थान पर बैठें। हाउस 12 बजे तक एडजॉर्न किया जाता है।

सदन पुनः अपराह्न 12.00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र गुप्ता जी को बुला लिजिए रूलिंग दे रहा हूँ।

माननीय नेता प्रतिपक्षः जी।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र गुप्ता जी को बुला लिजिए रूलिंग दे रहा हूँ। हां बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि बाद में दीजिए रूलिंग, मैं दे रहा हूँ। नहीं, नहीं बैठिए, बैठिए, उनको बुला लिजिए। कोई बात नहीं। महेन्द्र जी दो मिनट बैठिए, दो मिनट बाद। बहुतजरूरी विषय है। नहीं नहीं, मैं सदन को, देखिये महेन्द्र जी बैठ जाइए। दो मिनट बैठ जाइए, प्लीज। मैं, दो मिनट आप बैठिये, दो मिनट बैठिये, प्लीज। मैं, दो मिनट बैठिए जरा प्लीज। बैठिये, दो मिनट बैठिए, दो मिनट बैठिए। विजेन्द्र जी, महेन्द्र जी, दो मिनट बैठिए प्लीज। प्लीज बैठिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः महेन्द्र जी बैठिए दो मिनट भाई साहब। मैं आग्रह कर रहा हूँ बैठ जाइए, कमाल है। महेन्द्र जी मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ बैठिए। मेरा आग्रह स्वीकार करिये, बैठिए। महेन्द्र जी बैठिये प्लीज। आप बैठिये प्लीज बैठिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भाई जो सवेरे हंगामा हुआ। पहले एक सेकेंड रूक जाइए। चले गये जाने दीजिए। श्री विजेन्द्र गुप्ता माननीय सदस्य ने, भाई महेन्द्र जी बैठ जाइए कमाल है। मैं बार बार कह रहा हूँ।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आप बैठिये पहले।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः श्री विजेन्द्र गुप्ता जी माननीय सदस्य ने नियम 66 के तहत विशेषाधिकार हनन का नोटिस प्रातः 10 बजकर 59 मिनट पर विधान सभा सचिवालय में दिया था, जबकि नियमानुसार तीन घंटे पहले नोटिस दिया जाना जरूरी है। यह रूल बुक का पेज 31 है। इसको पढ़ लें। इसके बावजूद सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही श्री विजेन्द्र गुप्ता ने इस नोटिस के संबंध में हंगामा करना शुरू कर दिया। आश्चर्यजनक बात यह है कि उस नोटिस में आउटकम बजट का उल्लेख किया है। आउटकम बजट, मैं दोहरा रहा हूँ वार्षिक बजट से संबंधित कोई उल्लेख ही नहीं है। ये मेरे पास है उनका जो नोटिस आया हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि श्री विजेन्द्र का एक मात्र उद्देश्य सदन के समय को खराब करना था और इस तरह के आधारहीन नोटिस देकर सदन के समय को खराब करना और कार्यवाही में बाधा डालना इनकी पुरानी आदत है। इसके अलावा ये कोई जरूरी नहीं कि किसी नोटिस पर उसी दिन विचार किया जाए। हर नोटिस पर सोच-समझ कर निर्णय लिया जाता है और इस संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। मैं श्री विजेन्द्र गुप्ता जी को सख्त चेतावनी देता हूँ कि वे भविष्य में इसका ध्यान रखें और अनावश्यक तथा नियमों के विरुद्ध नोटिस

देकर सदन का समय खराब न करें। हर नोटिस का उत्तर देना संभव नहीं होता क्योंकि सदन का सूचीबद्ध कार्य को निपटाना हमारी प्राथमिकता होती है। इसके साथ-साथ मुझे ये भी कहना है..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः महेंद्र जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, एक सेकंड।

....व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं सुनूँगा,

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं सुनूँगा, एक सेकंड, एक सेकंड,

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अरे सारा समय आप खराब करते हों, आज आधा घंटा बेकार की बहसों पर खराब किया है, आधा घंटा, जिनको मालूम ही नहीं कुछ भी, उसको रूलिंग मालूम नहीं।एल.ओ. पी रहे हैं विजेंद्र गुप्ता। मैं बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा था उस समय, बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा था।

....व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः क्या ये सदन आप लोगों की बकवास सुनने के लिए तैयार बैठा है। आपकी बकवास सुनेगा हर बार।

....व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः महेंद्र जी, मैं समय दूँगा तब बोलियेगा।

....व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं आपके,..

....व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आपको..

....व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आप बोलिए महेंद्र गोयल जी, महेंद्र गोयल जी बोलिए, आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं।

....व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः एक सेकंड रूक जाए, एक सेकंड रूक जाइये।

श्री महेंद्र गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी।

....व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अरे भई मैं उनको समय दिया हैं न, बोलने दीजिए।

श्रीमती राखी बिरलाः अध्यक्ष जी, बात गंभीर है, ये सदन विपक्ष की फालतू बातों के लिए नहीं लगाया जाता, उनके ड्रामों के

लिए नहीं लगाया जाता, झूठा रंग घोलकर पानी में जो हंगामा करते हैं,

....व्यवधान...

श्रीमती राखी बिरला: पूरी की पूरी विपक्ष के लोगों को एक साल के लिए बाहर कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, सदन आपका साथ देगा..

....व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: ये विषय इतना महत्वपूर्ण था, महेंद्र जी आपने सारे विषय को खराब कर दिया।

....व्यवधान...

श्री महेंद्र गोयल: अध्यक्ष जी, मैंने खराब नहीं किया।

....व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: इतना महत्वपूर्ण विषय था।

....व्यवधान...

श्री महेंद्र गोयल: खराब वो कर रहे हैं।

....व्यवधान...

श्री महेंद्र गोयल: खराब वो कर रहे हैं।

....व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आपने मुझे तक पढ़ने नहीं दिया पूरा।

....व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मुझे पूरा पढ़ने नहीं दिया।

....व्यवधान...

श्री महेंद्र गोयलः अध्यक्ष जी,

....व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अब बोलिए, क्या कह रहे हैं, बोलिए।

....व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः आप उनको समय दे रहे हैं, मुझे भी दो मिनट दे दीजिए।

....व्यवधान...

श्री महेंद्र गोयलः अध्यक्ष जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, यहां 70-70 विधायक, इस विधान सभा के अंदर आते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। दिल्ली की जतना आज देखना चाह रही थी कि दिल्ली की जनता का बजट आज पेश होगा आपके सामने। केंद्र सरकार ने उसको रोक दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जिन सदस्य की आदत हर बार की है कि इस विधान सभा का टाइम वेस्ट किया जाए, आपने कई बार चेतावनी दे ली, आज से

नहीं मैं पिछले काफी समय से देख रहा हूँ, ऐसे सदस्य को इस हाउस के अंदर आने नहीं दिया जाए, ये आपसे अपील करता हूँ।

....व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः हो गयी बात पूरी। आपकी बात।

श्री महेन्द्र गोयलः मेरी बात सुनिये, अध्यक्ष जी, आप ही के द्वारा कितनी बार चेतावनी दी गई, पिछला रिकॉर्ड निकाल कर देख लो आप। जिस व्यक्ति की आदत बन गई है, आप अब भी बार–बार बुला रहे हैं, बताते हैं घर चले, अरे यहां पर क्या भाड़ भूनने के लिए आए थे वो।

माननीय अध्यक्षः नहीं आप कहना क्या चाहते हैं ये बताइये ना।

श्री महेन्द्र गोयलः मैं ये कहना चाहता हूँ। ऐसे सदस्य को इस विधानसभा में बैठने का हक नहीं होना चाहिए। उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए या कोई ना कोई सजा देनी चाहिए।

....व्यवधान...

श्री महेन्द्र गोयलः मैं कहता हूँ सत्ता पक्ष का भी करता है ना तो उसको भी बाहर कर देना चाहिए।

माननीय अध्यक्षः हो गया आपका। बोल लिया आपने और कुछ बोलना है।

श्री महेन्द्र गोयलः हां जी।

....व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः दिलीप पाण्डेय जी।

श्री दिलीप पाण्डेयः एक लिमिटेड सबमिशन अध्यक्ष महोदय मेरा भी है, जो विषय आपने पढ़ कर सुनाया जो शिकायत उस नोटिस में आपको दर्ज करा कर दी गई और जो तथ्य उसके साथ अटैच किये गए दोनों में मिसमैच है, कह कुछ रहे हैं सबूत कुछ और है, जिसे mala fide intent है ये तो समझ में आ रहा है। मेरा एक और आग्रह है, जो सदन के साथियों ने कहा उस बात में जोड़ते हुए मैं कह रहा हूँ, कि इस पूरे मैटर को Ethics Committee को भी रेफर किया जाए।

माननीय अध्यक्षः बताइये आप क्या कहना चाह रहे हैं।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत, अध्यक्ष महोदय

....व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं आप बोलिए आप क्या बोलना चाह रहे थे। नहीं आप बोलते रहिए। मैं सुन रहा हूँ। हां मैं सुन रहा हूँ ना। भाई साहब मैं सुन रहा हूँ। मैं सुन रहा हूँ ना।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः आप कुछ करो तो सही।

माननीय अध्यक्षः आप बोलिए ना मैं सुन रहा हूँ आपकी बात।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः आप देखें तो, रोकें तो सही।

माननीय अध्यक्षः आप बोलिए ना मैं सुन रहा हूँ।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अध्यक्ष जी ये क्या तरीका है।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः आप अनुमति दें।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण प्लीज ।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपको, ध्यान आपका एक घटना की ओर दिलाना चाहता हूँ। चौधारी प्रेम सिंह जी।

माननीय अध्यक्षः अरे भई इस विषय को बोलिए ना।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः इसी विषय पर बोल रहा हूँ, इसी विषय पर।

....व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः इसी विषय पर बोल रहा हूँ। चौधारी प्रेम सिंह स्पीकर थे और उस समय के वित्त मंत्री, श्री महेन्द्र सिंह साथी ने, दिल्ली विधानसभा में बजट कब पेश किया जाएगा, हाउस के बाहर तारीख की घोषणा कर दी और दिल्ली विधानसभा के स्पीकर ने फाइनेंस मिनिस्टर को पूछा कि आपने जो

तारीख अनाउंस की है जो तारीख आपने अनाउंस की है, क्या इस बजट को, ये बोलने नहीं दे रहे हैं, केन्द्र सरकार से अनुमति ली गई है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिये।

....व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आप बात क्या कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, विजेन्द्र गुप्ता की, विजेन्द्र गुप्ता की गुंडागर्दी की, आप ये कर रहे हैं।

....व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः हाउस दो बजे तक के लिए एडजर्न किया जाता है।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित की गई)

सदन अपराह्न 2:47 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्षः पहले वो खडे हुए हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं तो पहले खड़ा ही था। आपने मुझे बुलवाया।

माननीय अध्यक्षः मैं वो पढ़कर सुना चुका हूँ आपकी अबसेंट में।

....व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मेरी बात सुनिये। एक सैकेंड मेरी बात सुन लीजिए। मैं पहले वो पढकर सुना चुका हूँ। जो मैने ..

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए।

माननीय अध्यक्षः नहीं क्या कहना चाहते हैं। बैठिए बैठिए। बोलिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी आपने जो मेरा breach of privilege का नोटिस है उस पर उसकी जो ग्रहणता है उस पर आपने अपना फैसला दिया है। मैं जो रूल बुक है इसमें रूल 68 पढ़ रहा हूँ।

माननीय अध्यक्षः एक सैकेंड।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ग्रहणता की शर्तें

माननीय अध्यक्षः एक-एक चीज पर आ जाइये। दो मिनट रूकिये। आपका समय 10:59 है। आप एग्री करते हैं। 10:59 पर आपने नोटिस दिया।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः नहीं 10:59 पर नहीं है। ये पहले दिया है। उससे पहले दिया है। ये दोबारा रिसीव कराया है। एक सैक्रेट्री ऑफिस में हमने पहले दिया है।

माननीय अध्यक्षः वो सैक्रेट्री ऑफिस से रिकार्ड देख लिया। वहां..

श्री विजेन्द्र गुप्ताः नहीं-नहीं वो आप चैक कर लीजिए।

माननीय अध्यक्षः मैने चैक कर लिया है। चैक कर लिया है। अभी विजेन्द्र जी एक-एक चीज पर आप मैं बात कर लेता हूँ। दूसरा आपने इसमें आउटकम बजट की बात रखी है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः जी।

माननीय अध्यक्षः प्रूफ दिखाया है वो आउटकम बजट के नहीं दिखाया है। जहां तक रूलिंग की बात है, आपने स्वयं इस चीज को कहा था इसमें 66 में रूल 66 में..

श्री विजेन्द्र गुप्ताः सर मेरे को अपनी बात मुझे..आपने अपनी बात कह दी, मुझे कहने दीजिए फिर आप फैसला दे दीजिएगा।

माननीय सभापतिः नहीं आपने सुनी नहीं ना बात।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हाँ सुना दीजिए।

माननीय अध्यक्षः आप तो थे नहीं यहां। इसमें क्लीयर लिखा है at least three hours before कोई भी privilege motion आयेगा तीन घंटे पहले आना चाहिए। जिसकी आपने बात की मेरे ऑफिस में provided also that the Speaker may if he is satisfied with the urgency, I am not satisfied with the urgency अब आपको क्या कहना है बताईये।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, ये देश कानून से चलता है। ये हाउस भी कानून से चलता है। आप कानून के रक्षक हैं। अब मैं आपके सामने रूल 68 पढ रहा हूँ। क्योंकि अभी मेरी जो कम्पलेंट है वो आपके सामने admissibility पर उसका सवाल खडा हुआ है कि उसकी ग्रहणता जो है वो विषय है। रूल 68 क्या कहता है ग्रहणता की शर्ते ''ऐसे प्रश्न की ग्रहणता निम्नलिखित शर्तो से नियंत्रित होगी'' ये मतलब जो कमांड है इसकी admissibility की.

माननीय अध्यक्षः भई विजेन्द्र जी मैं इतना लम्बा नहीं जा रहा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक मिनट अध्यक्ष जी एक मिनट।

माननीय अध्यक्षः नहीं प्लीज। नहीं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आधा मिनट दीजिए।

माननीय अध्यक्षः एक सैकेंड। एक सैकेंड।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मुझे आधा मिनट तो दीजिए।

माननीय सभापतिः आज नहीं दो मिनट बैठ जाइये महेन्द्र जी। दो मिनट बैठ जाइये प्लीज। बैठ जाइये दो मिनट। मैं इससे आगे जाना नहीं चाह रहा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः नहीं आप मत जाइये। मेरे को बात तो कहने दीजिए।

माननीय अध्यक्षः मेरी कलम यहीं रूक रही है कि एटलिस्ट तीन घंटे पहले आना चाहिए था।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं वो ही कह रहा हूँ।

माननीय अध्यक्षः बस हो गया...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं अध्यक्ष जी एक मिनट।

माननीय अध्यक्षः पूरा मौका दे दिया।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये नाइंसाफी है।

माननीय अध्यक्षः सौरभ जी। प्लीज। हाँ कोई बात नहीं नाइंसाफी है। सौरभ जी बोलिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः देखिये.. विषय तक समिति हो..

....व्यवधान...

श्री संजीव झाः अध्यक्ष महोदय मैं इसी के संदर्भ में कुछ कहना चाह रहा हूँ। विजेन्द्र गुप्ता जी ने लगातार हाउस को disrupt किया है। इन्होंने जो नोटिस दिया था वो irrelevant notice है। उस पर आपने अपनी एक रूलिंग दी है। मेरा बस एक मात्र ये कहना है, मेरा बस एक ही निवेदन है.

माननीय अध्यक्षः सौरभ जी आप बैठिए।

श्री संजीव झाः एक साल तक इनको एक साल तक इनकी सदस्यता यहां से खत्म किया जाए। एक साल तक..

माननीय अध्यक्षः अरे वो कुछ बोल रहे हैं सौरभ जी।

श्री संजीव झाः एक साल तक इनको..

(समय की घंटी)

....व्यवधान...

श्री संजीव झाः इस सदन से इनको बाहर निकाला जाए। मेरा एक निवेदन है अध्यक्ष महोदय ये कोई पहली घटना नहीं है। बार-बार ये इस सदन को disrupt करते रहे हैं। आज भी एक irrelevant notice दिया जिसमें आपने अपनी रूलिंग दी। मेरा एक निवेदन है कि विजेन्द्र गुप्ता जी को एक साल के लिए इस सदन से बाहर निकाल दिया जाए।

माननीय अध्यक्षः ये प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इससे सहमत हैं वो हाँ कहें,

जो इससे असहमत हैं वो ना कहें।

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

विजेन्द्र गुप्ता जी को अगले बजट सेशन तक के लिए बाहर किया जाता है। नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिये।

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष जी, 23 तारीख का। अध्यक्ष जी, 23 तारीख का शहीद-ए-आजम भगत सिंह सुखदेव जी और राजगुरू

जी का शहीदी दिवस है और 23 तारीख को हमारा हाउस भी है। हम सभी विधायक अध्यक्ष जी उस दिन को बड़े उससे मनाना चाहते हैं उनके शहीदी दिवस के रूप में। तो श्रद्धांजलि के रूप में और सभी मनायेंगे उसको तो मैं चाहता हूँ कि उस दिन को कम से कम हाउस को ना रखा जाए। मैं चाहता हूँ यह प्रस्ताव सदन के सामने है जो इसके पक्ष में है वो अपनी बात रख सकते हैं।

माननीय अध्यक्षः 23 मार्च कुलदीप जी ने जो प्रस्ताव रखा है इससे जो सहमत हैं वो हाँ कहें जो इससे असहमत हैं ना कहें। (सदस्यों के हाँ कहने पर) 23 तारीख को सदन की बैठक नहीं होगी। भई मुझे काम करने दोगे या नहीं। वैसे ही आज सदन नहीं चल रहा है। बैठिए। सौरभ जी बैठिए अब। विजेन्द्र जी आपसे प्रार्थना है बाहर जाएं प्लीज। नहीं मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। अब करिये। मैंने बोलने का मौका दिया पूरा। ना हो गया। मैं आपको डिसअलाऊ कर रहा हूँ। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ जो सदन ने निर्णय लिया है। कुछ भी हो रहा है। ये अन्याय हो रहा है, जो मर्जी आये हो रहा है। वो आपकी इच्छा है मैं नहीं बोलूँगा। आप विजेन्द्र जी बाहर जाइये प्लीज। भाई साहब बैठ जाइये। तमाशा बना रखा है। बैठिए महेन्द्र जी। बैठ जाइये। प्लीज मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पूनर्विचार करना है नहीं करना है बाद में देखूँगा। अभी आप सदन को छोड़िये तो मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ विपक्ष की ओर से। रोज का तमाशा बन गया है, daily का जाइये, अभी आप छोडिये प्लीज। सदन को छोडिये। मार्शल्स विजेन्द्र जी

को बाहर करिये प्लीज। वो हाउस का समय खराब कर देते हैं बोलकर चिल्लाकर। चलिए विजेन्द्र जी अब नहीं। हाँ कोई बात नहीं। ज्यादती है ठीक है। भई आप मत बोलिये प्लीज।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो की दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं LOP रहे हैं उनको आपने सदन से बाहर निकाल दिया है इस घटना से हम बहुत दुखी हैं और दुखी होकर।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई आपने जो करना है करिये।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः मैंने आपसे पांच मिनट का समय मांगा था।

माननीय अध्यक्षः आपने जो करना है करिये।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः पांच मिनट का समय आपने मुझे दिया भी लेकिन रूलिंग पार्टी के ऑनरेबल मेंबर्स मेरी कुर्सी पर आ गये और जिस भाषा का इस्तेमाल किया मुझे इस उम्र में शोभा नहीं देता की मैं उसकी चर्चा भी करूं लेकिन अध्यक्ष जी यदि इस हाउस की मर्यादा को।

माननीय अध्यक्षः discussion on center has stopped to present the budget of Delhi Govt. उस पर डिस्कशन मैं आरंभ कर रहा हूँ श्री संजीव झा जी।

श्री संजीव झाः बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, यह एक गंभीर विषय है।

माननीय अध्यक्षः आप शुरु करिये अब, आप जारी रखिये।

श्री संजीव झाः यह गंभीर विषय है और यह चिंता का विषय भी है चूँकि आजादी के बाद से आज तक अगर हम जनतंत्र का इतिहास देखेंगे अगर पार्लियामेंटरी हिस्ट्री को देखेंगे न केवल देश का बल्कि अगर।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई संजीव झा जी बोल रहे हैं न।

श्री संजीव झाः न केवल देश का।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आप डायरेक्शन नहीं दे सकते आप बैठिये प्लीज।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः राखी जी प्लीज।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अध्यक्ष जी, ...

श्री संजीव झाः न केवल देश का बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है की किसी सरकार का किसी राज्य का।

माननीय अध्यक्षः मैं तो शांतिपूर्वक कह रहा हूँ आप बैठिये कार्यवाही में भाग लीजिए, कार्यवाही में भाग लीजिए चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। अब ये दिल्ली का बजट पेश नहीं हुआ इस पर चर्चा शुरु हो रही है चर्चा में भाग लीजिए नाम दीजिए मैं समय दूँगा।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः दिल्ली का तो बजट पेश ही नहीं हुआ तो फिर चर्चा किस बात की।

माननीय अध्यक्षः चलिये, क्यों नहीं पेश हुआ चर्चा नहीं होगी। बजट क्यों नहीं पेश हुआ इस पर चर्चा नहीं होगी आप उसमें बात कहिये अपनी, चलिये।

श्री संजीव झाः जैसा कि मैंने आपको पहले कहा की आजादी के बाद यह पहली बार ऐसा हुआ है की किसी राज्य का अपना बजट।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं वो मैं नहीं करूंगा किसी कीमत पर।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अध्यक्ष जी, जिस तरह से विजेंद्र गुप्ता जी को जैसे सदन से बाहर निकाला गया है हम उसके विरोध में सदन से वॉकआउट कर रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष जी।

श्री संजीव झाः किसी राज्य का जो बजट होता है वो उस राज्य के लिए हम सबके लिए एक उत्सव का दिन होता है तो

बजट का दिन निश्चित है इसकी घोषणा पहले से होती है, इसकी पूरी तैयारी होती है। फाइनेंस मिनिस्टर और उनके सभी अधिकारी दिन-रात काम करते हैं। हम सब लोग सदन के के सदस्य इंतजार करते हैं कि आज बजट आने वाला है लेकिन अचानक मैं न्यूज में देखता हूँ और पता यह चलता है कि दिल्ली सरकार का बजट पेश नहीं होगा। हमने फिर फाइनेंस मिनिस्टर साहब का हमने स्टेटमेंट देखा और वो जो स्टेटमेंट था वो बहुत चिंता का विषय है। वो चिंता का विषय इसलिए है की फाइनेंस मिनिस्टर को बजट पेश करना है और उनको जानकारी नहीं है कि इस बजट को रोक दिया गया है या इस बजट में कुछ आब्जर्वेशन की बात कही गई है। फाइनेंस मिनिस्टर भी जब न्यूज में देखते हैं उसके बाद जब अधिकारियों से बात होती है तब चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि हां केन्द्र सरकार का कुछ आब्जर्वेशन आया है। 10 तारीख को दिल्ली सरकार केबिनेट ने बजट को अप्रूवल करके केन्द्र सरकार को भेजा। जानकारी यह मिल रही है कि 17 तारीख को कोई आब्जर्वेशन आया और जो 17 तारीख का आब्जर्वेशन आया तो वो सूचना चीफ सेक्रेटरी के पास आता है। एक तो मुझे लगता है कि ये भी एक प्रक्रिया में भी हमारी शिकायत है की यह जानकारी चीफ मिनिस्टर साहब को होनी चाहिए थी, यह जानकारी फाइनेंस मिनिस्टर को होनी चाहिए थी लेकिन चीफ सेक्रेटरी को जानकारी मिलती है फाइनेंस मिनिस्टर को कोई जानकारी नहीं है, चीफ मिनिस्टर को कोई जानकारी नहीं है और चीफ सेक्रेटरी के पास जब जानकारी

आती है जो इतनी बड़ी इतनी वाइटल इनफार्मेशन है। अगर सही समय पर नहीं देने का नुकसान यह हो सकता है कि पूरी दिल्ली का जो कार्यपालिका है सब ठप्प हो जाएगी। जो काम कर रहे हैं उनको सेलरी नहीं मिलेगी। इतनी वाइटल इनफार्मेशन को चीफ सेक्रेटरी लेकर अपने घर बैठ जाते हैं। बजट के समय में चौबीसों घंटे अधिकारी काम करते हैं तो दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी इतना बेपरवाह कैसे हो सकता है कि इतनी वाइटल इनफार्मेशन को अपने मिनिस्टर से शेयर न करे। मुझे यह लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ी साजिश भी है। साजिश इसलिए की दिल्ली के एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी हमेशा हॉटलाइन पर रहते हैं ये पूरा दिल्ली प्रदेश जानता है। तो क्या एक निर्णय केवल चीफ सेक्रेटरी का था या एलजी आफिस का था या इस साजिश में केन्द्र सरकार शामिल है। मुझे लगता है कि अभी जी–20 के समय में पूरे वर्ल्ड से अलग–अलग राजनयिक देश में आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, important लोग आ रहे हैं। अभी मैं संसद में देख रहा हूँ किसी व्यक्ति ने कहीं कुछ बात बोल दिया तो देश का अपमान हो गया, जनतंत्र का अपमान हो गया संसद इस बात पर नहीं चल रही है। तो किसी एक व्यक्ति के बोलने से नहीं आपके कर्मों से जनतंत्र पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आज जब ये लोग इस देश में आए होंगे बाहर से लोग जब न्यूज देखे होंगे जब पेपर खोले होंगे तो पता चला होगा की केन्द्र सरकार अपने ही राज्य की राजधानी की जो सरकार है उसका बजट नहीं पेश करने दिया जा रहा है

तो देश का कितना अपमान होगा। मुझे लगता है कि लगातार केन्द्र सरकार ऐसी करतूतें कर रहा है जिससे इस देश का इस देश की जमहूरियत का, जनतंत्र का लगातार अपमान हो रहा है। एक से एक घोटाले हुए उस पर केन्द्र सरकार का कहीं कोई ध्यान नहीं। ईमानदार लोगों को जेल में बंद कर रहे हैं आप तो आपकी करतूत से इस देश का कार्यपालिका का विधयिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे चंद कुछ सवाल हैं एक की आज चीफ सेक्रेटरी 17 तारीख को अगर ये जानकारी आई अगर कुछ आब्जर्वेशन केन्द्र सरकार का था तो ये आब्जर्वेशन चीफ सेक्रेटरी ने फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से क्यों नहीं शेयर किया और अगर चीफ सेक्रेटरी या फाइनेंस सेक्रेटरी ने यह काम किया है जो असंवैधनिक है तो क्या केन्द्र सरकार कार्यवाही करेगी, क्या एलजी साहब कार्यवाही करेंगे और अगर एलजी साहब केन्द्र सरकार कार्यवाही नहीं करता है तो क्या यह साबित नहीं हो रहा है कि यह साजिश जानबूझकर केवल चीफ सेक्रेटरी आफिस में नहीं ये एलजी आफिस और केन्द्र सरकार के लोगों ने मिलकर के किया है। दूसरा किसी भी राज्य का जो बजट होता है वो सीक्रेट डाक्यूमेंट है। अगर वो जानकारी किसी अदना बाबू के हाथ लग जाए तो उसका नुकसान उस राज्य को हो सकता है चूँकि उसमें कई सारे ऐसे निर्णय हैं जो निर्णय केवल सदन के पटल पर आकर ही सदन पर टेबल होने के बाद ही उस पर चर्चा होती है। तो अगर कोई अदना बाबू उसमें से आब्जर्वेशन लगाकर के भेजता है तो क्या ये केन्द्र सरकार ये कहना

चाह रही है कि वो बाबू दिल्ली की चुनी हुई सरकार दिल्ली का जो विधानसभा है उससे वो ऊपर है तो मुझे लगता है की इसमें भी एक बहुत बड़ी साजिशें दिख रही हैं और इसका भी जवाब केन्द्र सरकार को देना चाहिये। ये जो न्यूज़ प्लांट कराया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब देते हैं ये पीठ के पीछे से न्यूज़ प्लांट करना क्या इस देश के जनतंत्र का अपमान नहीं है तो इसीलिये अध्यक्ष महोदय मेरा ये मानना है की आज केन्द्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता से बदला लेना चाह रहे हैं दिल्ली की जनता से क्यों बदला लेना चाह रहे हैं इनके तमाम झूठ तमाम चीज़ों का परोसा नफरत दिल्ली में आकर बोया लेकिन जब-जब चुनाव हुआ दिल्ली की जनता ने काम की राजनीति को सर्पोट किया काम की राजनीति के साथ खड़ा रहा तो अगर दिल्ली की राजनीति दिल्ली की जनता काम की राजनीति के साथ खड़ा है, विकास की राजनीति के साथ खड़ा है, अच्छे स्कूल अच्छे अस्पताल भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था को वोट कर रहा है तो आप दिल्ली की जनता का बजट रोककर उससे बदला लोगे आप, इतने गिर गये हैं आप तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा घृणित कोई दूसरा काम नहीं हो सकता तो इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले, आप अगर परमीशन दें, तो मैं एक संकल्प भी साथ में पढ़ना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्षः अब श्री संजीव झा माननीय सदस्य अपना संकल्प प्रस्तुत करने की परमीशन लेंगे। ''मैं संकल्प प्रस्तुत करने के लिये सदन की परमीशन चाहता हूँ'' यह प्रस्ताव सदन के सामने है।

श्री संजीव झाः अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करने के लिये सदन की परमीशन चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

सदन द्वारा संजीव झा जी को संकल्प प्रस्तुत करने की परमीशन दी गई अब श्री संजीव झा अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री संजीव झाः अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा दिनांक 21 मार्च, 2023 को दिल्ली में आयोजित अपनी बैठक में, जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण की प्रस्तुति एकमात्र एजेंडा बिंदू था, संकल्प करती है की इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जन समर्थक कार्यो के लिये बजटिय आबंटन को पटरी से उतारकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

की निर्वाचित सरकार के कल्याणकारी एजेंडे को किल करने की साजिश की गई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि मुख्य सचिव, वित्त सचिव और अन्य संबंधित अधिकारियों ने माननीय उप-राज्यपाल के कार्यालय और भारत सरकार की मिलीभगत से संबंधी सवांद को स्वेच्छा से दबा दिया है ताकि राष्ट्रीय राजधानी में वित्तिय संकट पैदा हो सके और इसे निर्वाचित सरकार की विफलता के रूप में चित्रित किया जा सके। इस बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करते हुये कि जिस तरह भारत सरकार दिल्ली के दो करोड़ से अधिक लोगों के खिलाफ इसलिये प्रतिशोध की कार्रवाई का सहारा ले रही है क्योंकि उन्होंने एक जन समर्थक सरकार चुनने का फैसला किया। कर सचांलन नियमों में असगंत्ता के प्रति चिंता व्यक्त करते हुये जो मौजूदा कानूनों और संवैधनिक प्रावधानों के साथ-साथ भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में दिनांक 4 जूलाई, 2018 को दिये गये एक फैसले के विपरीत है इस तथ्य से निराशा जताते हुये की वर्ष की वित्तीय विवरण जिसमें सर्वभौमिक रूप से एक दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया जाता है जब तक इसे विधान मंडल के सदस्यों को जांच और अनुमोदन के लिये सदन के पटल पर प्रस्तुत नहीं किया जाता वह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निम्नतम अधिकारियों की पूर्व जांच के अधीन है जो पूरी तरह असंवैधनिक और गैर कानूनी परम्परा है। दिल्ली और देश के प्रत्येक नागरिक का आवाह्न करती है की केन्द्र सरकार के तहत सक्रीय

जन विरोधी ताकतों की साजिशों को समझे, दिल्ली के दो करोड़ लोगों के खिलाफ भारत सरकार द्वारा की जा रही असंवैधनिक अवैध और अलोकतांत्रिक मनमानी की निंदा करती है, अनुशंसा करती है की निर्वाचित सरकार पर भारी अवैद्यतापूर्ण ढंग से लगाये गये असंवैधनिक और गैरकानूनी प्रतिबंधों को हटाने के लिये और निर्वाचित सरकार को सशक्त बनाने वाले संवैधनिक प्रावधानों का पालन करने के लिये कर संचालन नियमों में संशोधान किया जाना चाहिये। जैसा की भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सही ठहराया गया है और संकल्प करती है की मुख्य सचिव, प्रधान सचिव वित्त और अन्य द्वारा विधान सभा में बजट की निर्धारित प्रस्तुति में देरी में उनके आचरण और भूमिका को विस्तृत जांच और रिपोर्ट के लिये विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये।

माननीय अध्यक्षः यह संकल्प सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

श्री दिलीप पाण्डेः अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ आज जो इस सदन के सदस्य गुप्ता जी ने एक नोटिस दिया जिसके

ऊपर काफी विवाद हुआ, मुझे लग रहा है की ये एक पैटर्न सा बन गया है परिपाटी सी बन गई है आपने भी जो जल बोर्ड वाले वाले में हुआ जो पानी का खराब सैम्पल इन्होंने पेश किया पता चला वो सबकुछ बनाया गया था उसमें स्याही मिलाई गई थी तमाम चीज़ें हुईं मेरा मानना ये है की आपने जो रूलिंग दी वो तो सरमाथे है इस मसले को जो है Ethics Committee को भी फोरवर्ड किया जाये ताकि उस पर कुछ बातचीत हो सके।

माननीय अध्यक्षः श्रीमान दिलीप पाण्डे जी का ये प्रस्ताव ये विषय Ethics Committee को सौंप दिया जाये सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

अब ये विषय Ethics Committee को सौंपा जाता है।

माननीय अध्यक्षः राजकुमारी ढिल्लों जी।

श्रीमती राजकुमार ढिल्लोंः माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 'हजारों मंजिलें होंगी हजारों कारवां होंगे, निगाहें उनको ढूँढेगी ना जाने वह कहां होंगे'। अध्यक्ष जी, आज आज़ादी के बाद पहली बार दिल्ली

की चुनी हुई सरकार के बजट को केन्द्र में बैठी भाजपा सरकार द्वारा रोका जाना ना केवल गलत परम्पराओं को जन्म देता है बल्कि हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम को भी शर्मसार कर रहा है। माननीय उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व वाली सरकार के बारे में कहे गये शब्द शायद आज भाजपा को समझ नहीं आये। कुछ दिल्ली के उप–राज्यपाल के अभिभाषण की पंक्तियां जो की self-explanatory हैं कहने में मैं परहेज़ नहीं करूंगी। विभिन्न बाधाओं के बावजूद दिल्ली सरकार ने अनेक मोर्चों पर कई पहल की हैं और एक मज़बूत आधार तैयार किया है जिससे एक विकसित और समृद्ध दिल्ली बनाने में मदद मिलेगी यह self-explanatory line में सक्सैना जी ने जो बोली जहां पर उनके बारे में मैं कह रही हूँ। दिल्ली ही नहीं पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल की सराहना कर रहा है और यही कारण है की हमने अपने विकास मॉडल के कारण ना केवल दिल्ली में लोकप्रियता हासिल की अपितु पंजाब में चुनाव जीता। गुजरात में धामाकेदार एन्ट्री की और 10 वर्षों में अंदर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया। इन तमाम् बातों से केन्द्र में बैठी सरकार घबराई हुई है। आज देश के अंदर जिस प्रकार से लोकतंत्र का और संविधान का गला घोटा जा रहा है। भाजपा की सरकार बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को विकास के मॉडल पर न चलने दें। उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा है। उसका मुकाबला देश के अंदर श्री अरविंद केजरीवाल जी ही कर सकते

हैं। यही कारण है कि उनका सरकार के कामों को रोकने के लिए कभी सतेन्द्र जैन जी को कभी मनीष सिसोदिया जी को जेल भेजा जाता है और तो और हमारे विधायक भाईयों और बहनों को भी तरह तरह से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, जो केवल दिल्ली ही नहीं अध्यक्ष जी देश देख रहा है। दिल्ली के नागरिकों को मालूम था कि इस बजट के अंदर केवल दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर सर्वाधिक राशि खर्च करने का फैसला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कर रखा है और यही कारण है कि भाजपा सरकार की गृह मंत्रालय ने चौमुखी विकास वाले बजट को आज पेश जो होना था, रोकने का आदेश दे दिया, जोकि संविधान और लोकतंत्र के विरूद्ध है। मैं इस घिनौनी हरकत का विरोध करती हूँ और अंत में कुछ पंक्तियां बोलकर मैं अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूँगी:-

''हौंसले बुलंद कर, रास्तों पर चल दे,

तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा,

चलकर तु अकेला, पहल करके देख,

काफिला खुद बन जाएगा,

खोल दे पंख मेरे कहते हैं परिंदे,

अभी और उड़ान बाकी है जमीन नहीं हैं मंजिल मेरी,

अभी पूरा आसमान बाकी है,

जिंदगीभर टूटने का दर्द जिसको, झुका नहीं पाया,

हारकर खुद मौत ने जन्म दिन उसका मनाया,

हम उन्हें चुनौती देते हैं, जो बुझाने पर तुले हैं,

अरविंद केजरीवाल जी की सरकार वह दीपक है,

जिसे आंधियों ने खुद जलाया।''

धन्यवाद महोदय जी। इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने आज बोलने का मौका दिया है। बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।

माननीय अध्यक्ष: बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ऋतुराज जी। ऋतु जी, ऋतुराज जी संक्षेप में बोलिये वक्ता बहुत हैं। बहुत संक्षेप में, पांच मिनट से ज्यादा नहीं प्लीज।

श्री ऋतुराज गोविंद: ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आजाद भारत के इतिहास में आज काला दिन के रुप में जाना जाएगा। आजादी के 75 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक चुनी हुई सरकार का जो बजट है, उसको रोकने का काम भारत के एक अनपढ़ प्रधानमंत्री ने किया है, जिनको शायद पता नहीं है कि इस देश के अंदर में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए हमारे नेता जेल में रहे। 10-10 साल जेल में रहे अंग्रेजों के द्वारा ठुसे हुए जेल में रहे थे। हमारे भगत सिंह, राजगुरू, सुखदेव, अशफाकुल्ला खां फांसी के फंदे पर चढ़े थे, तब जाकर हमें आजादी मिली थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान

दिया ताकि हम सब आजाद रह सकें, सबको समानता का अधिकार मिल सके और ये देश लोकतंत्र, एक मजबूत लोकतंत्र के रुप में स्थापित हो सके। लेकिन आज का दिन ये काला दिवस के रुप में इसलिए मनाया जाएगा क्योंकि हमारे लोकतंत्र के अंदर में लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार ही सबकुछ होती है और दिल्ली के ढाई करोड़ लोगों ने एक सरकार को तीसरी बार चुना और ये सरकार हर साल सबसे पोपुलर बजट पेश करने के लिए जानी जाती है। पोपुलर बजट मैं इसलिए कह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, इस देश के अंदर में जितने भी राज्य है, बजट तो सबका पेश होता है, लेकिन चर्चा केवल और केवल पूरी दुनिया में दिल्ली सरकार के बजट की होती है। क्यों? क्योंकि एक मात्र सरकार है, जो पच्चीस प्रतिशत अपने बजट का शिक्षा पर खर्च करती है, स्वास्थ्य पर खर्च करती है। पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति की केवल बात नहीं करती है, उसके लिए काम करती है। पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का विकास कैसे हो, शिक्षा कैसे मिले, स्वास्थ्य कैसे हो, दवाईयां कैसे मिले और उसके जेब का खर्च कैसे ठीक से चले, घर परिवार कैसे चले, इसकी चिंता करती है और इस देश के अंदर में हो क्या रहा है। मतलब एक चुनी हुई सरकार का बजट को कोई रोक कैसे सकता है क्योंकि इनको डर किस बात का है। डर इस बात का है कि अगर दिल्ली के सारे बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो नाली में से जो गैस निकलता है, उससे चाय कौन बनाएगा। कोरोना के नाम पर थाली किससे बजवायेंगे, मूर्ख किसको बनायेंगे, भक्त

किसको बनवायेंगे, ट्रॉल आर्मी में किसको भर्ती करेंगे तो यहां पर देश के शाने में साफ साफ दिख रहा है। सारे देश को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से गुडागर्दी करके, हम लोगों को सर्टिफिकेट इन लोगों से नहीं चाहिए। आज 28-28 सालों से इनके एक राज्य में सरकार है। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम किया होता तो शायद इनको महत्व पता होता और शिक्षा का महत्व तो उस व्यक्ति को पता होगा जो खुद पढ़ा लिखा होगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीयेगा वो दहाड़ेगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। पर शिक्षा का महत्व तो उसको पता होगा जो शिक्षित होगा, जो शिक्षा की बात करेगा। ये अनपढ़ लोग, जिन्होंने एम.ए.इन. इंटायर पॉलिटिकल साइंस किया हो। एमए इनइंटायर पॉलिटिकल साइंस एक ही बार डिग्री पैदा हुई थी और एक ही व्यक्ति को मिला था और जो बिना टेलीपोर्टर का एक शब्द बोल नहीं सकता। किसी भाषण को कर नहीं सकता है। मतलब न्यूज चैनल वाले जो बुलाते हैं। इंडिया टूडे का कांक्लेव देख रहे थे, उसमें भी टेलीपोर्टर लगा हुआ था, उसी को देखकर भाषण कर रहे थे। मतलब उसमें भी कुछ गलत-शलत बोल कर चले गए, सारे देश के सामने एक्सपोज हो गए तो ये जो हो रहा है, ये सरासर एक गुंडागर्दी है और सरासर लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। ये दिल्ली का बजट है। ढाई करोड़ लोगों की उम्मीदें हैं। हर व्यक्ति टकटकी लगाये हुए हैं कि इस बार बजट में नया क्या होगा। शिक्षा में अलग क्या होने के लिए जा रहा है। स्वास्थ्य में क्या होगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या होगा। कच्ची कॉलोनियों के विकास के लिए क्या होगा, लेकिन जिस तरीके से गुंडागर्दी करके इन्होंने रोकने का काम किया है और ऊपर से षडयंत्र देखिये कहते हैं हमें ओब्जेक्शन लगाया है। अरे तुम्हारी औकात है क्या ओब्जेक्शन लगाने की। ओब्जेक्शन लगवाने वाले हो कौन तुम। दिल्ली की चुनी हुई सरकार बजट बनाती है और उस बजट को पास करने का काम दिल्ली की कैबिनेट करती है, जिसको कि दिल्ली की जनता ने चुना है। आप कौन हो ओब्जेक्शन लगाने वाले। अरे दिल्ली की सरकार तय करेगी कि कितना पैसा शिक्षा पर खर्च होगा, कितना स्वास्थ्य पर खर्च होगा, कितना प्रचार पर खर्च होगा। उसके प्रचार-प्रसार पर, कच्ची कॉलोनियों पर पानी की निकासी के लिए हो, पानी की लाईन बिछाने के लिए हो, सीवर लाईन के लिए हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, अस्पताल के लिए हो, मोहल्ला क्लीनिक के लिए हो, इतना पैसा किस चीज पर खर्च होगा, ये दिल्ली की चुनी हुई विधान सभा, कैबिनेट सरकार, मुख्यमंत्री तय करेगा। ये केन्द्र सरकार में बैठा हुए बाबू लोग नहीं तय करेंगे। वो अनपढ़ आदमी तय नहीं करेगा, जिसकी डिग्री खुद ही ़र्जी हो एमए इनइंटायर पॉलिटिकल साइंस से। हमारा बजट का भाषण..।

माननीय अध्यक्षः contents पढ़िए।

श्री ऋतुराज गोविंदः इसी विधान सभा में।

माननीय अध्यक्षः कंक्लूड करिये अब ऋतुराज जी कंक्लूड करिये प्लीज।

श्री ऋतुराज गोविंद: अभी पांच मिनट भी नहीं हुए।

माननीय अध्यक्ष: नहीं नहीं, हो गया। प्लीज।

श्री ऋतुराज गोविंद: इसी विधान सभा में ये साबित हो चुका था पिछले दो साल पहले की बात है। इसी विधान सभा का बजट का भाषण पहले से भाई साहब ने पढ़ दिया था, जिसको हम ही लोगों ने साबित किया था। हमारे बजट को तो आप फोलो करते आए। कम से कम ये मॉडल ही सीख लेते अभी तक इसकी जरूरत नहीं पड़ती।

माननीय अध्यक्ष: चलिए ऋतुराज जी कंक्लूड करिये प्लीज और

श्री ऋतुराज गोविंद: आज काला दिवस है। काला दिवस है लोकतंत्र के इतिहास में। 30 साल दिल्ली विधान सभा का हो गया। आजादी का 75 साल हो गये। आज तक किसी भी राज्य के बजट को रोकने का काम किसी ने नहीं किया। पर क्यों रोका गया है, छोटे छोटे ओब्जेक्शन लगाकर। कौन है चीफ सेक्रेटरी, कौन है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कौन अप्वाइंट करता है। इसको केन्द्र सरकार अप्वाइंट करती है और इसीलिए एक nexus करके, षडयंत्र करके इसको पूरे को किया गया है ताकि किसी भी तरीके से दिल्ली का बजट दिल्ली की विधान सभा में पेश न हो सके। दफ्तरों को तनख्वाह न मिल सके।

माननीय अध्यक्ष: बैठिये बैठिये ऋतुराज जी अब कंक्लूड करिये। बस हो गया प्लीज। प्लीज थैंक्यू so nice of you.

श्री ऋतुराजः बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः कुलदीप कुमार जी। कुलदीप जी पांच मिनट से ज्यादा नहीं।

श्री कुलदीप कुमारः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जैसा कि आज पूरे देश ने देखा अध्यक्ष जी कि अभी वक्ताओं ने अपनी बात यहां रखी कि किस प्रकार से आज का दिन सच में इस देश के लोकतंत्र के लिए और देश की डेमोक्रेसी के लिए काला दिवस है। अध्यक्ष जी आज तक किसी राज्य सरकार का बजट केन्द्र सरकार नहीं रोका अध्यक्ष जी। आज तक के इतिहास में कभी भी किसी चुनी हुई सरकार को किसी केन्द्र सरकार ने चैलेंज करने का काम नहीं किया। उसका बजट रोकने का काम नहीं किया। लेकिन अध्यक्ष जी कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री–नरेंद्र मोदी जी 18–18 घंटे काम करते हैं। अध्यक्ष जी, मुझे तो लगता है कि वो 18–18 घंटे में से 18 के 18 घंटे काम केवल इसलिए करते हैं कि कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री–अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम किया जाए, कैसे दिल्ली का काम रोका जाए, कैसे दिल्ली का विकास रोका जाए और अब तो हद यहां तक हो गई अध्यक्ष जी कि दिल्ली का बजट रोक दिया। इस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर उन्होंने इसका बजट रोकने का काम किया, जो इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, ये असंवैधनिक भी है और अध्यक्ष जी दिल्ली सरकार के कैबिनेट से पास हुआ बजट, दिल्ली के चुने हुए विधान सभा से पास हुआ बजट जो जाता है उसको देखने का काम एक बाबू कर रहा है,

वो बाबू बतायेगा ये बजट सही है या गलत है। जो दिल्ली के दो करोड़ लोगों ने सरकार चुनी, मुख्यमंत्री चुनें, कैबिनेट चुनी, ये उनका काम है, ये उनका काम थोड़ी है जो ऊपर बाबू बैठे हुए हैं। अध्यक्ष जी, राजा का राज खत्म हो चुका है, अब तो ये लोकतंत्र है, जनता के वोट से सरकार चुनी जाती है, राजा अब राज नहीं चलाता है कि राजा जी ने ऊपर से कोई आदेश किया और उनका आदेश पूरे देश में पालन हो जाएगा, अब ये लोकतंत्र है अध्यक्ष जी, ये डेमोक्रेसी है।

लेकिन आज जिस प्रकार से दिल्ली के दो करोड़ लोग ये आस लगाकर बैठे थे कि उनकी दिल्ली की उम्मीदों का बजट, स्वास्थ्य और शिक्षा का बजट, क्योंकि दिल्ली के बजट में हमेशा माननीय मुख्यमंत्री-अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के लिए कुछ न कुछ ऐसी योजना करते हैं जो दिल्ली के लोगों के लिए लाभान्वित होती है, उनको फायदा पहुंचाने का काम करती है। क्योंकि आज इस महंगाई के दौर में जहां केंद्र का पास हुआ बजट हमेशा आपको महंगाई की तरफ घुसेड़ देता है, लेकर जाता है, महंगाई बढ़ती जाती है, चाहे गैस की बात हो, चाहे दाल की बात हो, चाहे पेट्रोल की बात हो, चाहे डीजल की बात हो, वहीं दिल्ली के अंदर अध्यक्ष जी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सब्सिडी देना, उनको दवाइयां मुफ्त देना, साथ में बिजली सब्सिडी देना, दिल्ली की सरकार ये तमाम काम करने का काम करती है। लेकिन आज उन दिल्ली के दो करोड़ लोगों की उम्मीदों के बजट

को इस सरकार ने रोकने का काम किया, प्रधानमंत्री जी ने रोकने का काम किया और ये प्रधानमंत्री जी की अध्यक्ष जी आदत बन गई है, वो चाहते हैं दिल्ली का काम रूके, दिल्ली का विकास रूके।

हम तो पूछते हैं आखिर प्रधानमंत्री जी को इतना डर किस बात का है? आखिर प्रधानमंत्री जी इतना डरते क्यूँ हैं, वो घबराते क्यूँ हों? अरे आप देश के प्रधानमंत्री हों, आप इतना बड़ी पार्टी के नेता हों, आप एक छोटी सी पार्टी से डर गयें। एक इतनी छोटी पार्टी जिसकी दिल्ली में 70 में से 62 सीटें हैं, जिसकी पंजाब के अंदर 117 में से 92 सीटें हैं, जिसके राज्य सभा में 10 सांसद हैं, जिसके दिल्ली में नगर निगम में सरकार है, जिसके अब गुजरात के लोगों ने 40 लाख वोट दिया, आप इतनी छोटी पार्टी से डर गयें। और भाजपा वाले के पास क्या है दिल्ली में अध्यक्ष जी, 8 एम. एल.ए हैं इनके पास, बहुत बड़ी पार्टी है ये, इनके पास नगर निगम में सरकार नहीं है, इतनी बड़ी पार्टी है, पंजाब में तो एक या दो एम.एल.ए ही होंगेइनके पास, इतनी बड़ी पार्टी है और ये डरते हैं अध्यक्ष जी। इतना क्यूँ डरते हैं, इतना क्यूँ घबराते हैं? अरे जनता जब वोट देगी, चुनाव आयेगा, आप आइयेगा, आप भी योजना लेकर आइयेगा, आप भी खुद आइयेगा और चुनाव लड़ियेगा लेकिन आप बजट रोककर, दिल्ली का काम रोककर, दिल्ली की सड़कों का, नाली का, **(समय की घंटी)** सीवर का काम रोककर आप क्या दिखाना चाहते हों? आप दिल्ली के काम को रोककर क्या दिखाना

चाहते हों, आज देश आपसे ये पूछ रहा है अध्यक्ष जी? और एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा अध्यक्ष जी। ये देश इस बात को याद भी रखेगा कि लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर 2023 एक ऐसा साल था जब एक तानाशाह प्रधानमंत्री ने, जो अपने आप की तुलना हिटलर से करते हैं, जो अपने आपको हिटलर समझते हैं। बड़े-बड़े तानाशाह अध्यक्ष जी इस देश में आये हैं। बड़े-बड़े तानाशाह चले गयें इस दुनिया से और ये भी जायेंगे, जाना तय है, जाना निश्चित है और जाने की शुरूआत हो चुकी है अध्यक्ष जी, क्योंकि आज जिस तानाशाही से इस लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये रंगा-बिल्ला की जोड़ी ऊपर बैठी हैं न, इनका काम केवल ये ही होता है कि किसी भी तरह से जनता का काम रूके। सी.बी.आई लाओ, ई.डी लाओ, आई.टी लाओ, पुलिस लाओ, दिल्ली का काम रोको। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, कहकर अपनी बात खत्म करूंगा:

‘फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे,

फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे,

वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।’

अध्यक्ष जी, अरविंद केजरीवाल जी वो शमा हैं, वो व्यक्ति हैं कि आप कितना ही दबाने की कोशिश करोगे अध्यक्ष जी, वो हमेशा उतना उठेंगे ऊपर क्योंकि देश के लोगों का, दिल्ली की जनता का प्यार और आर्शीवाद उनके साथ है..

माननीय अध्यक्षः चलिए धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कुलदीप कुमारः क्योंकि दिल्ली के लोग उन्हें अपना बेटा मानते हैं और देशभर में उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से आज प्रधानमंत्री घबरा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का डर भी जायज है अध्यक्ष जी, मैं इस बात को कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री सोमनाथ भारती जी। समय की सीमा का ध्यान रखियेगा प्लीज।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस ज्वलंत मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, आज जो कुछ भी दिल्ली में घटा है ये भारतीय राजनीति के इतिहास में काला धब्बा है। एक चुनी हुई सरकार जो र्सिफ अपने कामों के कारण जानी जा सकी, देश में ही नहीं विदेशों में। आज इतनी बड़ी पार्टी, कहते हैं कि विश्व की सबसे पार्टी है और एक तरह से मान लें कि विश्व की सबसे छोटी पार्टी आम आदमी पार्टी है। इतनी घबराहट क्यूँ है आखिर ये? दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बजट पेश करने से रोका गया जबकि सबको पता था और पिछले 10 साल से होता आ रहा है। 10 मार्च को ये बजट एम.एच.ए में अप्रूवल के लिए भेजा गया जोकि एक नेचुरल प्रोसेस है, उसका रूकना और रोकना किसी भी एंगल से वाजिब नहीं है, असंवैधनिक है। 17 तारीख को ऑब्जेक्शंस आयें, जो ऑब्जेक्शंस तुरंत पेश किये जाने चाहिए थे मंत्री जी को,

उसे 20 तारीख को दिया शाम को 6 बजे, ये जो घटना घटी है इसे हम संवैधनिक अपराधा कह सकते हैं, ये constitutional crime है। अध्यक्ष महोदय, इनको चिढ़ क्या है? ये क्यों हमसे घबराते हैं?

मोदी जी को 30 साल लग गये, 30 में भी, 30 साल से सरकार चला रहे हैं गुजरात में, लेकिन एक स्कूल नहीं था दिखाने को जब माननीय केजरीवाल जी गयें गुजरात में। तो चूँकि competitiveness में आना, उनको आना पड़ा तो टेंट में स्कूल बनवाया, 30 साल में एक स्कूल नहीं बनवाया, टेंट में स्कूल बनवाया और उसके बाद जब मीडिया वाले ढूँढ़ने गये तो स्कूल गायब मिला, ये है उनकी घबराहट। घटना क्या घटी है, अगर साथी याद करें अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस, बी.जे.पी जब शासन में हुआ करती थी आम आदमी पार्टी के पहले तो जनता को कभी विश्वास नहीं होता था कि कुछ काम करेंगे ये लोग। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी के आने से एक जो घटना घटी है पूरे देश में और दिल्ली में, लोग कहने लगे हैं कि हो तो सकता है, स्कूल अच्छे हो तो सकते हैं, अस्पताल अच्छे हो तो सकते हैं, बिजली मुफ्त आ तो सकती है, बिजली 24 घंटे आ तो सकती है, पानी मुफ्त आ तो सकता है, बस राइड मुफ्त मिल तो सकता है लेकिन ये भा.ज.पा, कांग्रेस के हाथों नहीं हो सकता, ये केजरीवाल के हाथों हो सकता है, ये ही मुसीबत है उनको, ये ही मुसीबत है उनको। अगर हम भी उनके तरह, हमारे सारे जितने साथी बैठे हैं, हम भी उनके तरह अपने कट-बिजनेस में लग गये होते, एक corrupt

व्यवस्था का, सिस्टम का हिस्सा हो गये होते, इनको मुसीबत नहीं थी। आज केजरीवाल जी के नाम के साथ एक जो चीज जुड़ी है और जो पूरे भारत में आग की तरह फैल गई है वो ये है कि कर तो सकता है यार, लेकिन करेगा तो केजरीवाल करेगा, आम आदमी पार्टी करेगा, इनके हाथों नहीं हो सकता, ये ही मुसीबत है इनकी।

एम.सी.डी के अंदर 134 की संख्या 104 से बड़ी है, इतनी मामूली सी गणित बताने के लिए आम आदमी पार्टी को जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया भा.ज.पा को कि भाजपाइयों गणित जानो, 134 बड़ा है 104 से, तब जाकर के ये दिमाग में घुसा कि हां भैया 134 बड़ा है 104 से, ये रहा है इनका, एक सुप्रीम कोर्ट तभी तो अरविंद जी कह रहे हैं कि भैया पढ़ा-लिखा प्रधानमंत्री चाहिए कि अनपढ़ चाहिए, नहीं तो ये ही करता रहेगा ये। अब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भई 134 बड़ा है 104 से, तब जाकर के दिल्ली को मेयर मिला, डिप्टी मेयर मिला, फिर फंस गये वहां स्टैंडिंग कमेटी में।

अध्यक्ष महोदय इन्होंने जो कुछ भी किया है ये संवैधनिक अपराधा है, देश देख रहा है, देश समझ रहा है, देश के लोग जान रहे हैं किस प्रकार से बाबा साहब का दिया गया संविधान आज शर्मसार हो रहा है, मतलब सोचिये 70 मे से 62 सदस्यों वाली पार्टी उसपे भाजपा दे रही है 'नो कोन्फिडैन्स मोशन'। क्योंकि एक साथी ने बड़ा अच्छा कहा, इसका मतलब खरीदने के लिए

पैसा आ चुका है, सीबीआई, ईडी लग चुका है, मतलब ये हास्यास्पद है जो भाजपा करती है, जो कहती है, कि 70 सदस्य विधानसभा के अंदर जो 62 सदस्य पार्टी है।

माननीय अध्यक्षः बस सोमनाथ जी कन्क्लूड करिये।

श्री सोमनाथ भारतीः उसकी सरकार को 'नो कोन्फिडैन्स मोशन' दे रही है बीजेपी।

माननीय अध्यक्षः बस सोमनाथ जी कन्क्लूड करिये प्लीज।

श्री सोमनाथ भारतीः अपने आप में हास्यास्पद है। आज जो कुछ भी हुआ है, इस सदन के अंदर, आज बजट सेशन था, अब इस प्रकार से मतलब ये समझिये कि जो माननीय केजरीवाल साहब रोज-रोज कह रहे हैं, तो माननीय मोदी जी प्रूव कर रहे हैं सिद्ध कर रहे हैं कि हां भईया हम तो अनपढ़ हैं। चुंकि एक अनपढ़ व्यक्ति ही संविधान में साफ-साफ लिखा गया जो प्रोविजन्स हैं उसको समझता नहीं है। आज उसने साथी ने कहा कि भईया, वो चाय बनवाया नाले से गैस निकाल कर, कहा कि भईया रॉकेट जो है साथियों वो बादल में रडार नहीं पकड़ेगा उसको, तो हमने सोचा इस पार अच्छा रहेगा, कि जब बारिश हो रही हो, तब भेज देते हैं पाकिस्तान पर अटैक करने को। फिर कहा कि भईया नोटबंदी से करप्शन खत्म हो जाएगा। टेरिरिज्म खत्म हो जाएगा।

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी कन्क्लूड करिये प्लीज, सोमनाथ जी कन्क्लूड करिये अब।

श्री सोमनाथ भारती: एक मिनट, अब ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष: 6 मिनट आपकी हो गईं

श्री सोमनाथ भारती: ये सभी प्रमाण हैं कि देश को एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए भईया, और वो एक ही आदमी है और वो केजरीवाल है अरविंद केजरीवाल।

माननीय अध्यक्ष: चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सोमनाथ भारती: चुंकि मैंने एक, एक सेकण्ड और मैंने जब से मुझे माननीय केजरीवाल साहब ने नोमिनेशन दिया है वाइस चेयरमैन जलबोर्ड का, मैं बैठना शुरु किया मिटिंग्स में, मैं देख के हैरान हूँ अध्यक्ष महोदय। I want to bring this on record एक-एक चीज माननीय मुख्यमंत्री को जानकारी है कौन सा ट्यूबेल, कितना आउटपुट, कितना हॉर्सपावर का मोटर कौन सा lathe, कितना इनपुट, कैसे पानी साफ होगा, मैं तो इतना ही impressed हूँ, ऐसा व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो देश को भारवर्ष को कोई विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद धन्यवाद।

श्री सोमनाथ भारती: मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और ये जो मोशन साथी ने मूव किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

माननीय अध्यक्षः श्री राजेश गुप्ता जी।

श्री सोमनाथ भारतीः ये पास हो ये जो वित्त सचिव ने और मुख्य सचित ने जो गलती की है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़े। थैंक यू।

श्री राजेश गुप्ताः अध्यक्ष जी जिस विषय पर आपने बोलने के लिए कहा है और सभी साथी बोल भी रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही कि सब बोल–बोल के हमें फायदा क्या हो रहा है, जब भी अखबारों में आता है। मैं आपके माध्यम से जो भी इसे कवर करते हैं दिल्ली विधानसभा को उनसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो ये ना दिखायें के दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के अंदर झगड़ा क्या है, बल्कि उन तथ्यों को रखें कि दरअसल दिल्ली की चुनी हुई सरकार, जनता ने सरकार को चुन लिया, दिल्ली की जनता ने मोदी जी को बता दिया कि 'दिल्ली लव केजरीवाल'। उसके बाद में पाँच साल तो मिलेंगे ना, उस पाँच साल के अंदर हमने बजट बनाया, दिल्ली की जनता की जो महत्वकांक्षा थीं जो आकांक्षाए थी दिल्ली सरकार के साथ में उसके हिसाब से बनाया, कि एजूकेशन में वो क्या चाहती है, जब हम आंदोलन करते थे तो लोग कहते थे कि देश में पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। अरविंद जी ने उसे नोट कर लिया, लोगों ने कहा अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो बहन बेटियों के जेवर बिक जाते हैं, अरविंद जी ने इस बात को नोट कर लिया। लोगों ने कहा दिल्ली की सफरक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है क्योंकि दिल्ली की पुलिस

दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को अगर जवाब नहीं देगी तो दिक्कत होगी। अरविंद जी ने उसके लिए धारना दिया कि भईया पुलिस नहीं दे रहे हैं तो कैमरे तो लगने दो, तब जाकर वो कैमरे लगे। अब आप उस बजट को रोक लोगे जिस बजट की खुशी के अंदर दिल्ली की जनता ने तीन बार एक मुख्यमंत्री को चुना वो बजट अच्छा था इसीलिए चुना ना। हमने जो एलोकेशन करी अपनी मर्जी से आज तक नहीं करी। जनता ने चाहा उस पर काम किया दिल्ली की जनता खुश है। अब रोज-रोज रोज-रोज तंग करना जैसा साथियों ने कहा कि मेयर का चुनाव मत होने दो। वहां मारापीटी करते हैं। पानी फेंकते हैं, समान उठा कर फेंक रहे हैं, अरे वहां हम 134 हैं ये 104 हैं हमने तो ऐसा व्यवहार नहीं किया यहां हम 62 हैं आप सिर्फ आठ हो और हम सब बहुत जवान हैं, लेकिन हमने आपकी, पूरा सम्मान रखा आप 8 हो हमने किसी ने हाथ लगाया कभी आपको, हमने कोई बदतमीजी करी, हमने खुद आप पर फेंक के मारा हमने तो कुछ नहीं करा, हमने आपका सम्मान करा। आप आठ भी हो तो क्या बात है दिल्ली की जनता ने आपको चुना है हमने उनका सम्मान करा। हमने विपक्ष का दर्जा दिया, लेकिन आप वहां पर मारापीटी करते, क्योंकि आप हो तो हमसे कम, लेकिन सौ के आस-पास आ गए हैं गलती से तो दिल्ली की जनता को वहां भी बता रहे हैं कि काम नहीं होने देंगे। ये क्या तरीका है तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बातें हैं रोज क्योंकि दिल्ली के अंदर इतने अखबार छपते हैं, एक-एक चीज

पे बात हो जो हम कह रहे हैं हम पढ़े लिखे लोग हैं हमारे साथियों ने बात को रखा, हमारे मुख्यमंत्री पढ़े लिखे हैं हम चाहते हैं कि अनपढ़ लोग जो बैठे हैं जो देखते हैं कि दिल्ली में झगड़ा हो रहा है अरे भई ये झगड़ा कर रहे हैं सत्ता के लिए, ये झगड़ा कर रहे हैं काम ना हो हम झगड़ा कर रहे हैं दिल्ली के अंदर काम हो, हम चाहते हैं हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, हम चाहते हैं कि हमारे घर में कोई बीमार हो जाए तो उसको सस्ती दवाईयां मिल जाएं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, लेकिन इसी बातों से इन्हें दिक्कत है। ये बताएं हमारे आस–पास के अंदर हरियाणा है इनकी सरकार है, यूपी है इनकी सरकार है, मधयप्रदेश है इनकी सरकार है। आप देख लीजिए कि अगर दिल्ली के आस पास के जो पेरीफेरी में जो हॉस्पिटल्स दिल्ली सरकार के आप चलिए जीटीबी आपके पास में एक हॉस्पिटल है, जहां के आप विधायक हैं उसके पास में आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास गाजियाबाद के कितने लोग आते हैं उसमें, क्योंकि वहां हॉस्पिटल है ही नहीं, यूपी के अंदर। आप चलिए नजफगढ़ की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, बहादुरगढ़ के सारे मरीज, झज्जर के मरीज उसी के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में है ही नहीं। आप चलिए नरेला के अंदर अस्पताल है आप देखिये उसमें कहां के लोग आ रहे हैं सारे के सारे दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं। तो जो इनको दिक्कत है के जो ट्रोल आर्मी जो इन्होंने बनानी है जो बिना सोचे समझे बकवास करेगी, किसी

पिक्चर को बैन कर दो, ऐसे शोर मचा दो, वहां जाकर धारना दे दो, वो लोग इनको नहीं मिल पाएंगे अगर ये पढ़ लिख जाएंगे। तो मैं आखिरी बात कहते हुए आपसे कहता हूँ कि कल से अखबार वालों से एक रिक्वेस्ट है कि गहन चर्चा करें, वो भी पढ़े लिखें हैं और इन topics को सिलसिलेवार तरीके से रखें जो तकलीफ हमारी है जो हमारा कहना है कि केन्द्र सरकार हमारी बात नहीं मानती हमारी बात में चर्चा करें, पढ़ें लिखें और फिर उसको छापें। आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। संजीव भाई ने जो प्रस्ताव रखा है मैं पूरी तरीके से उसका समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्रीमान राजेन्द्र पाल गौतम जी।

श्री राजेन्द पाल गौतमः धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्षः आप ये पाँच मिनट में कंप्लीट करिये प्लीज।

श्री राजेन्द पाल गौतमः मैं चार में कर देता हूँ।

माननीय अध्यक्षः करिये।

श्री राजेन्द पाल गौतमः मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः मैं धन्यवाद करुंगा, बहुत-बहुत धन्यवाद करूंगा।

श्री राजेन्द पाल गौतमः एक्चुअली हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हो क्यों रहा है। बजट जहां तक मेरी स्टडी है मैं पोलिटिकल

साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। आज तक भारत सरकार में, किसी भी राज्य सरकार में इस तरह बजट रोकने की कोई घटना अभी तक तो देखने में नहीं आई है और ये अगर सिलसिलेवाइज पूरी स्टडी करें, जब से दिल्ली में 2013 में बदलाव हुआ और उसके बाद जो लगातार घटनाक्रम है। अगर हम कड़ियों को जोड़कर देखते हैं तो ये समझ आता है कि ये दिल्ली की सरकार के साथ दिल्ली की जनता के साथ वॉर है। ये वॉर केंद्र सरकार स्वयं और आपने नुमाइंदे, उपराज्यपाल और साथ-साथ कुछ चुनिंदा ब्यूरोक्रेट को साथ में ले कर ये वॉर कर रही है, मैं सरकार का हिस्सा होने के नाते, जो मैंने स्टडी किया जो-जो ऑफिसर दिल्ली की सरकार के जनता के काम को रोकते हैं, उन्हीं ऑफिसर्स को बहुत अच्छे-अच्छे विभागों में प्रमोशन दिया जा रहा है और जो ऑफिसर सरकार के साथ कॉपरेट करते हैं इमानदारी से जनता के लिए काम करते हैं, उन ऑफिसर को कहीं ना कहीं पनिशमेंट दिया गया हैं।

तो जब इस पूरी प्रक्रिया को देखता हूँ और अभी पिछले एक सप्ताह पहले मैं कुछ प्रोफेसर साथियों के साथ बैठा था। अचानक मेरे मैंने उनसे कहा कि वो ये लगता है कि इस बार हो सकता है कि ये बजट भी दिल्ली का रोकने का प्रयास करें, तो सारे प्रोफेसर कहने लगे कि भारत के इतिहास में संभव नहीं है। भारत के संविधान के माध्यम से देश चल रहा है और बजट पे तो विपक्ष भी चुप रहता है। शांति से बजट को पास करने देता है और जब कल शाम अचानक मैंने मुख्यमंत्री जी का एक टीवी

चैनल पे वो पढ़ा, सुना तो मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि जो मैं कह रहा था ये तो वो ही हो गया। तो ये बेसिकली दिल्ली की जनता ने जो बीजेपी को आइना दिखाया और काम करने वाले लोगों को आगे बढ़ाया, देश को तोड़ने की साजिश करने वाले जाति, धर्म के नाम पे उन्माद करने वाले बाबा साहिब के बनाए संविधान को खत्म करके मनुस्मृति का शासन भारत में लाने का प्रयास करने वाले पार्टी को दिल्ली की जनता ने punish किया। उसका बदला केन्द्र सरकार दिल्ली की जनता से ले रही है और ये बेहद शर्मनाक है और केवल दिल्ली के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे जहां-जहां विपक्षी सरकारें हैं इन्होंने डीएमके की सरकार को परेशान किया। इन्होंने ठाकरे की सरकार को परेशान किया। इन्होंने झारखण्ड की सरकार को परेशान किया जो प्रस्ताव वहां के सदन ने पारित किया, असेम्बली ने पारित किया उसको राज्यपाल ने रोक के रखा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन पे जो अपने सदन के अंदर पास करके प्रस्ताव भेजा आज तक भी उस प्रस्ताव को वहां के राज्यपाल ने रोक के रखा हुआ है। जबकि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। राज्यपाल पुनर्विचार के लिए तो भेज सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता उसको रोक के बैठ जाए। तो इस तरह जिस तरह पूरे देश की विपक्षी पार्टियों को जो-जो सत्ता में हैं उनके काम को जिस तरह आज केंद्र की सरकार स्वयं या आपने राज्यपालों के माध्यम से उपराज्यपालों के माध्यम से रोक रही है। मैं समझता हूँ इससे देश के संविधान

के खिलाफ एक ऐसा लगता है उसके खिलाफ ही एक वॉर चल रहा है और इसमें पूरे देश के लोगों को समझना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी मैं समझता हूँ सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालयों की है।

माननीय अध्यक्षः गौतम जी कन्कलूड करिये प्लीज।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः और मुझे लगता है कि पूरा देश देख रहा है। देश की न्यायालय भी देख रहे हैं। जल्द ही कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा और हम सब मिलके इस तरह की गतिविधियों का विरोध करेंगे और ये प्रस्ताव संजीव झा जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्रीमान राजकुमार आनन्द जी।

माननीय समाज कल्याण मंत्री (श्री राजकुमार आनन्द): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जो आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया है। अध्यक्ष महोदय इस सत्र में एलजी साहब ने अपने अभिभाषण की शुरूआत 'मेरी सरकार' कहकर की जो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये सुनकर बहुत खुशी हुई लेकिन गृह मंत्रालय को शायद ये बात रास नहीं आई और उन्होंने उनके द्वारा नियुक्त किये हुए उपराज्यपाल को भी मतलब उनको ये लगा के उनके द्वारा नियुक्त किये गए उपराज्यपाल को भी मजबूरन दिल्ली सरकार की तारीफ करनी पड़ रही है। इतनी बंदिशों के बाद

भी अगर अरविन्द केजरीवाल इतना बढ़िया काम कर सकते हैं तो उन्होंने दो दिन के अंदर ही पलटा मार दिया और जो मेरी सरकार यहां पर एलजी साहब कह रहे थे दो दिन के बाद तेरी सरकार कहने लगे। अध्यक्ष महोदय एलजी साहब ने अपने अभिभाषण में जो काम गिनाए वो सारे के सारे दिल्ली सरकार के काम हैं। ये काम वो हैं जो दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी के नेतृत्व में किये गए। आज गृह मंत्रालय दिल्ली सरकार को बजट पेश करने से रोक रहा है। लेकिन अपने काम पर अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान नहीं दे रहा है। दिल्ली के लॉ एण्ड ऑर्डर को मेनटेन करने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। आज दिल्ली के लॉ एण्ड ऑर्डर का क्या हाल है किसी से छिपा नहीं है। गृह मंत्रालय को इस बात की खबर होनी चाहिए कि दिल्ली चोरी, हत्या और नशा खोरी का शहर बनता जा रहा है। juvenile क्राइम और ड्रग माफिया इस शहर को खोखला बनाते जा रहे हैं। आज juvenile क्राइम, पॉकेट मारी और स्नैचिंग से बढ़कर हत्या तक पहुंच गया है। आज दिल्ली में कई ऐसे अपराधी गिरोह सक्रिय हो गए हैं जो कम उम्र के बच्चों को किशोरों को नशे की लत लगाते हैं और फिर उनसे बढ़े-बढ़े क्राइम करवाते हैं। अगर दिल्ली में juvenile क्राइम को नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं है जब हम दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहना हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं सदन के माध्यम से गृह मंत्रालय से पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली शहर में जन सफरक्षा के लेकर जो अव्यवस्था फेली है उसके लिए

कब जांच कमेटी बैठेगी, उस पर कब छापे पड़ेंगे, उस पर कब सवाल पूछे जायेंगे। अध्यक्ष महोदय आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे स्याह दिन है। जब जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को अपना बजट पेश करने से रोका जा रहा है। ये अरविन्द केजरीवाल की सरकार, दिल्ली की सरकार का अपमान नहीं है,ये दिल्ली की आम जनता और उसके दो करोड़ वोटरों का अपमान है।ये बाबा साहिब अंबेडकर द्वारा लिखे हुए संविधान का अपमान है, जनतंत्र को अपमान है, लोकतंत्र को अपमान है। वो हमें बजट पेश करने से रोक रहे हैं। इसका साफ-साफ मतलब है कि वो दिल्ली के अस्पतालों के डॉक्टरों की तनख्वाह रोकना चाहते हैं। वो दिल्ली के स्कूलों के शिक्षकों की तनख्वाह रोकना चाहते हैं। वो बुजुर्गों और डिसेबल्स की पेंशन्स को रोकना चाहते हैं जो उनके जीने का सहारा है। वो सफाईकर्मियों की तनख्वाह को रोकना चाहते हैं। वो डीटीसी बसों को रोकना चाहते हैं। वो उन बसों में फ्री सफर करने वाली आधी आबादी को रोकना चाहते हैं। वो दिल्ली सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को रोकना चाहते है। वो अरविन्द केजरीवाल और उनके विजन को रोकना चाहते हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी को ये पता लग गया है कि कांग्रेस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये छोटी-सी पार्टी आम आदमी पार्टी ही उनको एक दिन हरायेगी ये उनको पूरी तरह से समझ में आ चुका है। और इसी वजह से हमारे मंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और हमारे ऊपर तमाम तरह के अनैतिक काम किये जा रहे हैं। लेकिन

मैं उनको बता देना चाहूँगा कि अरविन्द केजरीवाल जी का वीजन उनकी विचारधारा वो खुशबू है, जिसे रोका नहीं जा सकता। आज इस खुशबू से दिल्ली महक रही है। पंजाब महक रहा है। कल पूरा देश महकेगा। मैं चार लाइनों के बाद अपनी बात खत्म करूंगा। यूँ ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नई है ना अपनी रीत नई यूँ ही हमने हमेशा खिलाए हैं आग में फूल ना उनकी हार नई है, ना अपनी जीत नई बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः अब माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी।

माननीय विकास मंत्री (श्री गोपाल राय): माननीय अध्यक्ष महोदय ये दुर्भाग्य है कि आज सदन में बजट प्रस्तुत होना था और आज ये सदन इस बात पर चर्चा कर रहा है कि बजट क्यों नहीं प्रस्तुत हुआ। अध्यक्ष महोदय कई साथियों ने कई महत्वपूर्ण बातें आपके समक्ष रखी हैं इस सदन के समक्ष रखी हैं। लेकिन आज बजट प्रस्तुत ना होना जिसको लेकर के पूरे देश के अंदर लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर चुनी हुई सरकार आज अगर अपना बजट प्रस्तुत करना चाहती थी तो क्यों नहीं कर पाईं अध्यक्ष महोदय जो आज बजट प्रस्तुत नहीं हो रहा है और जिस तरह इस बजट को रोकने के लिए समझी बुझी रणनीति के तहत केंद्र सरकार माननीय लेफ्टीनेंट गर्वनर, दिल्ली के चीफ सेकेट्री, दिल्ली के फाइनेंस सेकेट्री का जो पूरा एक चक्रव्यूह बना और आज बजट प्रस्तुत नहीं हुआ। ऐसा नहीं बजट प्रस्तुत नहीं होगा,

बजट तो प्रस्तुत होगा। आज गृह मंत्रालय ने उसको सैंक्शन किया, बजट प्रस्तुत होगा, लेकिन उसको क्यों किया गया। ये इस बात को दिखाने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि ताकत हमारी है। हमारे इशारे के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। उनकी तमन्ना है कि एक पत्ता भी हिलेगा तो उनके आदेश से हिलेगा। लेकिन दर्द भी उनको यही है कि हवायें उनके आदेश को नहीं मानतीं।

अध्यक्ष महोदय, इस घटना ने एक और खुलासा किया है। पिछले 8 महीने से टेलीविजन चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता प्रवक्ता से लेकर के प्रधानमंत्री तक घूम घूम के इस बात को कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई इस लिये हो रही है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार इसलिए किया गया कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार इसलिये किया गया कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। अध्यक्ष महोदय, रंगा सियार बहुत दिन तक शेर बनकर के नहीं रह सकता। कल बजट के रोकने की कार्यवाही ने ये साबित कर दिया कि दिल्ली के लोगों के खिलाफ दिल्ली सरकार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, दर्द ये है कि हमारी इच्छा के बगैर दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत्ती कैसे है, हमारी इच्छा के बगैर मुख्यमंत्री इतना अच्छा काम कैसे करता है, हमारी इच्छा के बगैर पूरे हिन्दुस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा क्यों होती है, दर्द इस बात का है। रंगा सियार का सब रंग उतर गया और

मसला अध्यक्ष महोदय, एक दिन का नहीं है। दिल्ली के अंदर जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी आपको याद होगा आम आदमी पार्टी की सरकार ने जब अपना काम करना शुरू किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा कि ये काम इसलिये हो रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में एक प्रधान सचिव बैठा हुआ है शायद उसके दिमाग से ये काम हो रहा है। दर्द पैदा हुआ, आदेश पारित हुआ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय पर सीबीआई का छापा डाला गया। नाजायज़ तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय के प्रधान सचिव को परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, उससे भी काम नहीं रूका, काम बढ़ता रहा। उसके बाद इनको लगा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी बिठा रखे हैं, उन पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की वजह से काम आगे बढ़ रहा है। पार्लियामेंट सेक्रेटरी के निरस्त करने के लिये, उनकी सदस्यता बर्खास्त करने के लिए सारा षडयंत्र रचा गया, कोर्ट से सारे लोग बहाल हुए और वो षडयंत्र फेल हुआ। फिर उनको लगा कि यार फिर भी काम चल रहा है, पार्लियामेंट सेक्रेटरी हट गये फिर भी काम चल रहा है। उसके बाद अध्यक्ष महोदय फिर काम रोकने के लिये शुंगलु कमेटी बिठाई गयी। एक एक फाईलों को, एक एक फाईलों को, चप्पे चप्पे को, एक एक लफ्ज को पढ़ा गया, छाना गया, दूरबीन लगाकर के। सारी फाईलें एलजी हाउस में पड़ी हुई थी। कुछ नहीं निकला। फिर भी काम आगे बढ़ गया। अध्यक्ष महोदय, ये घटनाक्रम दिखा रहे हैं कि जो दर्द है वो दर्द इसी बात का है कि इस

दिल्ली के अंदर तेजी के साथ एक ऐसी सरकार है जो काम भी करती है और ईमानदारी के साथ अपने उसूलों पर टिकी भी रहती है, ये दर्द है जिस दर्द की वजह से सारी कार्रवाईयां हो रही हैं। आप एक बार समझने की कोशिश करिये चुनी हुई सरकार अपना बजट प्रस्तुत करना चाहती है और बजट को रोक दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, अब तो सारी हदें पार हो गयी हैं। पहले एलजी के माध्यम से फिर सेंटर गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके दिल्ली के अधि कारों को, कामों को जब कत्लकरने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि दिल्ली के एलजी के पास लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस के अलावा कोई पावर नहीं है, सारा निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास है, चुनी हुई सरकार के पास है। उसके बाद भी जिस तरह से जब सरकारी अधिकारियों को एलजी बनाकर के काम नहीं किया गया तो पॉलिटिकल व्यक्ति को एलजी बना करके भेजा गया और जब से नए एलजी साहब आए हैं जिस तरह से सारे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सारे टीबीआर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो किसी से छुपा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बात केवल विधान सभा के अंदर की नहीं है। जिस तरह से दिल्ली के लोगों ने नगर निगम में चुनाव करके बहुमत से आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का मैनडेट दिया ये छुपा नहीं है भ्रष्टाचार नहीं था वहां, जिस तरह से तीन तिकड़म करके सत्ता का दुरूपयोग करके एलडरमैन बनाकर के सदन में

एमसीडी के चुने हुए प्रतिनिधि बैठे रहे और एलडरमैन को गन प्वाईंट पर शपथ दिलाई जा रही थी, भ्रष्टाचार हो रहा था वहां पर। क्या दर्द था केंद्र सरकार का। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का आदेश दिया कि एलडरमैन वोट नहीं दे सकते और आज दिल्ली के अंदर मेयर चुना जा सका है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ दिल्ली के अंदर जिस तरह से संविधान, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर के आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है अध्यक्ष महोदय, भारत का इतिहास रहा है हम बर्दाश्त करते हैं तो अंतिम सांस तक बर्दाश्त करते हैं लेकिन जिस दिन मुकाबला करने के लिये खड़ा हो जाते हैं उस दिन जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था उनके राज में, उनका भी अस्त कर देते हैं, हम उन्हीं पुर्खों के बेटे हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, ये मजबूर किया जा रहा है। इस देश को मजबूर किया जा रहा है, पूरे देश के अंदर जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है हम चाहते हैं कि लोकतंत्र का सम्मान हो, संविधान का सम्मान हो, देश का सम्मान हो लेकिन अगर कोई अपनी इच्छा की बदौलत, अपने अहंकार की वजह से इस देश की सारी संस्थाओं को, सारी मर्यादाओं को कुचलने की अगर कोशिश करेगा तो वो दिन दूर नहीं है दिल्ली के लोग भी और इस देश के लोग खत्म करेंगे जिस सत्ता के नशे में ये सब कुछ हो रहा है उस सत्ता को चकनाचूर कर देंगे अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।

माननीय अध्यक्षः रामवीर सिंह बिधूड़ी जी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली विधान सभा में दिल्ली का बजट पेश होना था। रूलिंग पार्टी की ओर से केंद्र सरकार और दिल्ली के ऑनरेबल एलजी के उपर अनेक तरह के आरोप लगाये गये हैं। मैं मर्यादा में रहते हुए अपनी बात को कहूँगा। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को बजट की फाईल 9 तारीख को भेजी, ऑनरेबल एलजी ने कुछ क्वेरिज़ लगाईं, उसी दिन दिल्ली सरकार को फाईल लौटा दी गयी। क्वेरिज़ के बारे में ऑनरेबल सीएम को मालूम था 10 तारीख को फाईनेंस डिपार्टमेंट ने क्वेरिज़ के बारे में ऑनरेबल फाईनेंस मिनिस्टर को भी जानकारी दी। जो क्वेरिज़ लगाई गयी थी उन क्वेरिज़ को रिमूव करके बजट की फाईल मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स को भेजी जा सकती थी। लेकिन क्वेरिज़ रिमूव नहीं की गयी। 17 तारीख को मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स ने बजट की फाईल दिल्ली सरकार को भेज दी। अब यदि दिल्ली के ऑनरेबल फाईनेंस मिनिस्टर उसके लिए भी अपने अधिकारियों को दोष दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि सिस्टम जो है पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है। आप केंद्र सरकार को भी गाली निकालेंगे, आप ऑनरेबल एलजी को भी गाली निकालेंगे और एलजी ने यदि कोई क्वेरिज़ लगाई हैं तो उनके पास संवैधनिक अधिकार है। उस अधिकार के चलते लगाई गयी हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, बजट लीक कर दिया जाता है, दिल्ली के ऑनरेबल फाईनेंस मिनिस्टर ने

गोपनीयता की शपथ ली है और उसके बावजूद बजट लीक हो जाये तो क्या अपोजिशन की ड्यूटी नहीं बन जाती है कि हम दिल्ली के फाईनेंस मिनिस्टर का इस्तीफा मांगें। क्या यदि दिल्ली की सरकार क्वेरिज़ को रिमूव नहीं कर पाईं और फिर उसका दोष दिल्ली सरकार के अधिकारियों के उपर मढ़ा जाता है, केंद्र को और एलजी को गाली निकाली जाती है, क्या ये इस प्रजातंत्र के लिये ठीक होगा। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक नहीं है। सच्चाई ये है स्पीकर साहब कि दिल्ली की सरकार अनेक भ्रष्टाचारों से घिरी हुई है।

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। देश की एकता अखंडता को खतरा उत्पन्न हो गया है। पंजाब में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, कानून व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई है। लोगों की अटैंशन डायवर्ट हो करने के लिए ये सारा नाटक किया गया है। ये सारा नाटक किया गया है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः विधूड़ी जी आप, चर्चा किस बात पे हो रही है।

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः सारा नाटक किया गया है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चर्चा किस बात पे हो रही है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः सारा नाटक किया गया है ये।

माननीय अध्यक्षः नहीं चर्चा किस बात पर हो रही है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः सारा नाटक किया गया है।

माननीय अध्यक्षः मैं पूछ रहा हूँ चर्चा किस बात पर हो रही है। चर्चा किस बात पर हो रही है। आप शांति से, चर्चा किस बात पर हो रही है। आप पंजाब पहुंच गए, चर्चा किस बात पर हो रही है।

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः सुनने का माद्दा नहीं है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अरे भई मैं पूछ रहा हूँ चर्चा किस बात पर हो रही है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः हमने डिस्टर्ब नहीं किया, हमने ऑनरेबल स्पीकर साहब।

माननीय अध्यक्षः बिधूड़ी जी मैं पूछ रहा हूँ चर्चा किस बात पर हो रही है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः जी।

माननीय अध्यक्षः चर्चा किस बात पर हो रही है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः चर्चा हो रही है कि आज बजट पेश नहीं हो सका।

माननीय अध्यक्षः बस उस पे चर्चा रखिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः आप जा रहे हैं पंजाब पर, वहां पर, वहां पर क्या तमाशा है ये? नहीं एलओपी हैं आप। आप एलओपी हैं। एलओपी की मर्यादा समझिए, एलओपी की मर्यादा समझिए आप।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः मेरी सजा तय कर देना यदि मैं हाउस में गलत बयानी कर रहा हूँ। देखिए,

माननीय अध्यक्षः क्या तमाशा है ये?

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी।

माननीय अध्यक्षः नहीं क्या तमाशा है हम काम की बात कर रहे हैं।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी।

माननीय अध्यक्षः अब कंक्ल्यूड करिए आप अपनी बात।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने।

माननीय अध्यक्षः आप कंक्ल्यूड करिए। मैं और समय नहीं दे रहा।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः मैं कंक्ल्यूड कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्षः कंक्ल्यूड करिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः मैं।

माननीय अध्यक्षः कंक्ल्यूड करिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अब ना मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ ना दिल्ली की बात कर रहा हूँ। मैं एक बात कह के अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्षः करिए?

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः भईया सुन तो लो ना।

माननीय अध्यक्षः बोलिए, बोलिए, बोलिए क्या कहना है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं देखिए, श्रीमती शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे महेंद्र सिंह साथी और चौधारी प्रेम सिंह दिल्ली विधानसभा के स्पीकर थे।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बोलने दीजिए भई, बोलिए, बोलिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: और फाइनेंस मिनिस्टर ने हाउस के बाहर बजट कब पेश होगा उसकी तारीख एनांउस कर दी। केन्द्र सरकार से अनुमति नहीं आई थी, दिल्ली विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष चौधारी प्रेम सिंह ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से और दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर से एक्सप्लेशनेशन कर ली थी और दिल्ली की चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित को और दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर महेंद्र सिंह साथी को स्पीकर के सामने माफी मांगनी पड़ी थी, ये है स्वस्थ परंपरा। यदि बगैर केन्द्र की अप्रूवल के बजट की तारीख तय की गई, एनाउंस की गई आप फाइनेंस मिनिस्टर का इस्तीफा लीजिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: चलिए बैठिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: बहुत बहुत धन्यवाद।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी चर्चा का उत्तर देंगे।

माननीय मुख्यमंत्री (श्री अरविंद केजरीवाल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय आज इस हाउस में दिल्ली का बजट पेश होना था, केन्द्र सरकार ने कल शाम को उस बजट के उपर रोक लगा दी। आज दिल्ली विधानसभा के अंदर बजट पेश नहीं हो पाया। इसके उपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं।

...व्यवधान...

माननीय मुख्यमंत्रीः इसके उपर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान लिख रहे थे उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि ये एक ऐसी सिचुएशन भी, संविधान जो है वो तरह तरह की सिचुएशन से डील करता है, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ऐसी सिचुएशन भी इस देश के अंदर आ सकती है कि केन्द्र सरकार किसी राज्य सरकार के बजट को रोक भी सकती है। एक ऐसा कंस्टीट्यूशनल क्राइसिस मैं तो कहूँगा ये कंस्टीट्यूशनल क्राइसिस भी नहीं है It is an attack on the constitution of this country इस देश के संविधान के उपर हमला किया गया है। ये कहा जा रहा है ये डेट सारी बताई जा रही हैं। दस तारीख को, दिल्ली सरकार ने बजट सैन्टर को भेजा, 17 तारीख को सैन्टर ने कुछ ऑब्जेक्शंस लगा के वो बजट दिल्ली सरकार को भेजा, अभी माननीय लीडर आफॅ अपोजिशन साहब कह रहे थे कि एलजी साहब ने कुछ ऑब्जेक्शंस लगाए, संविधान के अंदर एलजी को कोई ऑब्जेक्शन लगाने का अधिकार नहीं है। He is bound by the aid and advice of the council of Ministers सुप्रीम कोर्ट का आदेश है

...व्यवधान...

माननीय मुख्यमंत्रीः एक मिनट, एक मिनट मेरे को पूरा। मैं एक मिनट पूरी कर लेता हूँ। एक मिनट।

...व्यवधान...

माननीय मुख्यमंत्री: लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं ऑब्जेक्शंस नहीं ऑब्जर्वेशंस, चलो कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट का 2018 का आर्डर साफ-साफ कहता है, संविधान का आर्टिकल 239(एए)(4) साफ साफ कहता है 'That Lt. Governor of Delhi or the Administrator of Delhi is bound by aid and advice of Council of Ministers.' दिल्ली के Lt. Governor जो हैं वो केवल ठप्पा लगायेंगे तीन सब्जेक्ट्स छोड़ के, बाकी सारी चीजों को उनको बस ठप्पा लगाना है। वो अपनी ऑब्जर्वेशन भी नहीं दे सकते, ऑब्जेक्शन भी नहीं दे सकते, वो फाईल पे कुछ नहीं लिख सकते। उनको फाईल पे लिखने का अधिकार नहीं है। अगर वो फाईल पे कुछ लिखते हैं तो वो संविधान के खिलाफ है। अगर वो फाईल पे लिखते हैं तो वो इस मंदिर का, ये जनतंत्र को जो मंदिर है इसका अपमान है, इस पूरे हाउस का अपमान है। कुछ कहना है तो ये हाउस कहेगा, ये हाउस किसलिए बैठा है। ये जितने लोग हैं चाहे ये बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, इनको जनता ने चुन के भेजा है फिर ये किसलिए चुने गये हैं। अगर एलजी ने ही दिल्ली चलानी थी तो? अगर केंद्र सरकार के पास बजट भेजा गया, केंद्र सरकार को उसमें आपति करने का कोई अधिकार नहीं है। ये प्रोविजन ही un-constitutional, it is against the basic structure of democracy and basic structure of the constitution of India कि किसी राज्य का बजट केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है पर चला आ

रहा है कई सालों से। जिस दिन इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया ये दो मिनट ये प्रोविजन नहीं टिकने वाला कि केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार का बजट भेजा जा रहा है। और एक परंपरा चली आ रही है। कई सालों से चली आ रही थी हम भी उस परंपरा को फालो कर रहे थे। आज तक दिल्ली के इतिहास में कभी केंद्र सरकार ने कोई ऑब्जेक्शन या ऑब्जर्वेशन नहीं किया। पहली बार ये परंपरा जो है इसको तोड़ा गया, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा के भेजे, ऑब्जर्वेशंस लगा के भेजे, वही अपने आप में असंवैधनिक था। लेकिन हमें लड़ना नहीं है। हम लड़ना नहीं चाहते, हम यहां लड़ने नहीं आये हैं हम काम करने आये हैं। सत्रह तारीख को उन्होंने भेजा। चीफ सेक्रेटरी के पास भेजा, र्प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाईनेंस के पास भेजा। तीन दिन वो लेके बैठे रहे। अब सारा देश जानता है कि इन अधिकारियों की गर्दन जो है वो केंद्र सरकार और एलजी के अंदर में है, रोज जिसको मर्जी सस्पेंड कर देते हैं, सारे डरे बैठे हैं। सारे डरे बैठे हैं अधिकारी, वो बेचारे क्या करें। तो उपर से आदेश आया एमएचए से कि भई तीन दिन तक लेके बैठे रहो, सोमवार को 20 तारीख को, 21 को बजट प्रजेंट होना था 20 तारीख को दिन में दो बजे मंत्री को बताया जाता है जी एमएचए से कुछ ऑब्जेक्शंस आये हैं तो इन अधिकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिये? फाईल जो है उसके संबंध में उसके बाद बार बार फोन कर रहा है मंत्री, फाईल उसके पास शाम को छह बजे पुटअप की गयी। उसके बाद अफरातफरी के

अंदर मंत्री ने नोट बनाया, जो भी ऑब्जर्वेशन थे हमारे पास एक ऑप्शन था हम लड़ लेते, कोर्ट चले जाते कि तुमने ऑब्जर्वेशन कैसे लिखे, पर मैंने मंत्री को कहा नहीं हमें लड़ना नहीं है। उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन लिखे हैं चार ऑब्जर्वेशन थे चारों का हमने जवाब लिखा, कोई चेंज नहीं किया बजट में, सेम बजट, ईगो थी कि हमारा जवाब दो, दे दिया भाई साहब। आपके पैर छू लिये, पैर छू लिये उनके, उनके सामने हाथ जोड़ लिये, जो मांगा उन्होंने जवाब दे दिये, आज वापस आ गया है बजट अप्रूव हो गया। अहंकार ही है। क्या मिल गया?

...व्यवधान...

माननीय मुख्यमंत्री: एक मिनट, एक मिनट सर एक मिनट। आप ही की जिंदाबाद है सर पूरी आप ही हो बस। बाकी हम तो ऐसे ही हैं। क्या मिला इससे? यही मिला जो ये अभी कह रहे हैं जिंदाबाद, बस यही राजनीति है, अहंकार है। खुश हो गये भई केजरीवाल को झुका दिया। हांजी हम तो हमेशा ही झुके हुए हैं।

जनतंत्र में झुकना ही एक, जनता के सामने भी झुकना चाहिये, सबके सामने झुकना चाहिये। अहंकार सैटिसफाई करने के अलावा कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कल ये मैं देख रहा था, टीवी चैनलों में चल रहा था कि इन्होंने इन्फ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा एडवर्टाइजिंग का बजट कर दिया, हमने इनको ठीक करने को बोला है। यही चल रहा था ना टीवी चैनलों में। की जी एडवटाईजिंग का बजट

इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा कर दिया, हमने इनको ठीक करने को बोला है। उसमें बजट के अंदर बीस हजार करोड़ तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, 500 करोड़ एडवरटाईजिंग पर है। अब ये 500, बीस हजार से ज्यादा होता है ये तो हमने नहीं सुना था। इन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक अनपढ़ों की जमात बैठा रखी है।

...व्यवधान...

माननीय मुख्यमंत्रीः मैंने आपके नेता को नहीं कहा, मैंने आपके नेता को नहीं कहा, आपको कैसे लगा उसको बोला है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बैठिए, बैठिए, बैठिए। हाँ ठीक है, अच्छा है कर दिया।

...व्यवधान...

माननीय मुख्यमंत्रीः मैंने तो नाम ही नहीं लिया, मैंने तो नाम ही नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया।

माननीय अध्यक्षः बैठिए, बैठिए, बैठिए।

माननीय मुख्यमंत्रीः मैं किसी का नाम.

...व्यवधान...

माननीय मुख्यमंत्रीः मैं तो ये कह रहा हूँ जी, ये बता दो की कहां लिखा है कि 500 की फीगर जो है वो 20 हजार से ज्यादा होती है। ये तो कहीं नहीं लिखा। तो मैं कह रहा हूँ भई, जो पूरी की पूरी अनपढ़ों की जमात बैठा रखी है, पढ़े–लिखे लोगों को बैठाओ वहां पर, ताकि वो कम से कम बजट पढ़ने की क्षमता तो रखते हों। पता नहीं किसको दे दिया आपने बजट। 500 करोड़ रुपए पिछली साल रखा था, 500 करोड़ रुपए इस साल रखा है, सेम है सेम टू सेम है, कोई बढ़ाया नहीं हमने, एज इट इज बजट रखा है। कहते हैं कल से चला रखा है, भई बजट, एडवर्टाजिंग का बजट बढ़ा दिया, एडवर्टाजिंग का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा। कहाँ कर दिया, कहीं नहीं करा। आज वो सेम टू सेम बजट हमने कोई चेंज करके नहीं भेजा, जो बजट में लिखा था उसी में से 4 लाइनें कोट कर–करके भेज दी। आज एल जी साहब ने भी, कल रात को साढ़े 10 बजे लिख दिया, अप्रूवड। अरे ये क्या है यार। तो पहले ही अप्रूव कर देते, क्या जरूरत थी। वो कह रहे थे मेरे सामने झुको, मेरे पैर पकड़ो। आपके सामने झुक गए भाई साहब। आप ही प्रभू हो, आप ही सबकुछ हो। मेरी आज इस मंच के, इस हाउस के माध्यम से अपील है, प्रार्थना है प्रधानमंत्री जी को, कि प्रधानमंत्री जी हम काम करना चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते। हमारी लड़ाई हमारे बस की बात नहीं है, हम बहुत छोटे लोग हैं। राजनीति में हम लड़ने के लिए नहीं आए, हमें राजनीति करनी नहीं आती। इस रोज–रोज की लड़ाई से कुछ नहीं निकल

रहा। जिस घर में लड़ाई होती है, वो घर बर्बाद हो जाते हैं। जिस राज्य में लड़ाई होती है वो राज्य बर्बाद हो जाते हैं, जिस देश में लड़ाई होती है, वो देश बर्बाद हो जाते हैं। लड़ाई से किसी का कहां भला हुआ है। कभी भला हुआ है। सबसे बनकर रखनी चाहिये, सब मिलजुल के काम करेंगे तरक्की होगी। दिल्ली ने इतना, आज मैं अखबारों में पढ़ रहा था, कल हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने इकोनोमिक सर्वे प्रजेंट किया, इतनी तरक्की की दिल्ली ने। देश का जो एवरेज है उससे कहीं ज्यादा आगे जाकर तरक्की कर रही है दिल्ली। इतनी तरक्की कर रही है, इतनी तरक्की कर रही है। सोचो अगर ये रोज-रोज के झगड़े नहीं होते तो, दस गुणा तरक्की हो चुकी होती अभी तक, जितनी तरक्की अभी तक हमने कर ली। हमारा डोर स्टैप डिलीवरी राशन करना चाहते थे हम, वो रोक दिया। किसका फायदा हुआ? जो राशन वाले चोरी करते थे, राशन माफिया था उसका फायदा हुआ। जनता का फायदा तो नहीं हुआ। क्या फायदा हुआ उसका। डोर स्टैप डिलीवर ऑफ राशन रोकने का। दिल्ली के अंदर 17 हजार लोगों को डेली हम योगा कराया करते थे, डेली 17 हजार लोगों को दिल्ली सरकार फ्री में योगा कराती थी। प्रधानमंत्री जी ने कह कर वो योगा क्लासिस बंद करा दी। किसका फायदा हुआ जी। किसी का तो फायदा नहीं हुआ। 17 हजार लोगों ने अगर योगा करना बंद कर दिया। आज भी याद करते हैं मेरे को, मिलते हैं, आज भी याद करते हैं, किसका फायदा हुआ, किसी का फायदा नहीं हुआ।

हम अपने टीचर्स को, दिल्ली का शिक्षा, जो व्यवस्था है उसकी तारीफ पूरे देश के अंदर हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे टीचर्स और हमारे प्रिंसिपलस ने चमत्कार करके दिखाया है, 60 हजार टीचर्स उन्होंने चमत्कार करके, उनको हम ट्रेनिंग करने के लिए विदेश भेजते हैं, फिनलैंड भेजते हैं, आपने उनकी फिनलैंड की ट्रेनिंग रोक दी। किसका फायदा हुआ, किसी का फायदा नहीं हुआ, गरीबों के बच्चे अच्छे पढ़ना चालू हुए थे, बड़े, इतने 75 साल के बाद गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चालू हुई थी। क्या फायदा हुआ। टीचर्स की ट्रेनिंग रोकने से किसका फायदा हो रहा है, क्यों लड़ रहे हो हमारे साथ यार। पिछले साल कई महीनों तक मोहल्ला क्लीनिक में टैस्ट की पेमेंट बंद करा दी, रैंट की पेमेंट बंद करा दी, बिजली के बिलों की पेमेंट करा दी, दवाईयों की पेमेंट बंद करा दी। मोहल्ला क्लीनिक में अस्पतालों में, कितने मरीज सफर किए, कितने मरीज सफर किए। किसका फायदा हुआ, किसी का फायदा नहीं हुआ। फरिश्ते स्कीम थी, किसी का एक्सीडैंट हो जाए तो उसको हम फ्री में इलाज कराया करते थे। 13 हजार से ज्यादा जान बचा चुके हैं उस स्कीम के अंदर हम लोग। उस स्कीम की पेमेंट बंद करा दी, बताओ उस स्कीम की पेमेंट बंद करा दी। मरते हुए आदमी को अगर हम जान देने की कोशिश कर रहे थे, उसकी पेमेंट बंद करा दी, किसका फायदा हुआ प्रधानमंत्री जी। अभी जैसा हम लोग देख रहे हैं कि बजट रोक

दिया, मेयर के चुनाव बंद करा दिये। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, आप बहुत बड़े हैं, हम बहुत छोटे हैं। एक छोटी सी दिल्ली चला रहे हैं, हमें अपनी दिल्ली चलाने दो, आप बहुत बड़े हो, बहुत बड़ा-बड़ा काम कर रहे हो, पूरे देश के अंदर काम कर रहे हो। आप अपना काम करो ना, हमें अपना काम करने दो। उनको तकलीफ ये है कि दिल्ली में बार-बार, बार-बार आम आदमी पार्टी क्यों जीत रही है। उनको तकलीफ ये है कि बार-बार, बार-बार दिल्ली में बीजेपी क्यों हार रही है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि अगर आप दिल्ली जीतना चाहते हो, तो मैं आज आपको मंत्र देता हूँ दिल्ली जीतने का। दिल्ली जीतने के लिए आपको दिल्ली के लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। ये रोज-रोज लड़ाई-झगड़े करने से दिल्ली वाले आपको वोट नहीं देने वाले। मैंने अगर दिल्ली में हजार स्कूल ठीक कर दिए, आपके पास तो बहुत पैसा है, आप हजार नए स्कूल बना दो, देखो लोग केजरीवाल को वोट देना बंद कर देंगे। मैंने दिल्ली में 550 मोहल्ला क्लीनिक बना दिए, आप साढ़े पांच हजार मोहल्ला क्लीनिक बना दो। लेकिन अगर आप केजरीवाल के 550 मोहल्ला क्लीनिक रोकने की कोशिश करोगे, अगर आप हमारे स्कूलों को रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूँ, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। हमसे लम्बी लकीर खींचो। जो काम हमने किए उससे लम्बी लकीर खींचो। आज इस पूरे सदन की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, हम आपके साथ मिलकर काम करना

चाहते हैं, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हमारे को लड़ाई करनी नहीं आती, हमको राजनीति करनी नहीं आती, हम आपसे मिलकर काम करना चाहते हैं, आपसे सहयोग चाहते हैं। हम बहुत छोटे हैं। जैसे परिवार में होता है। दिल्ली के लोग जो हैं, आपके सामने छोटे भाई की तरह हैं। लेकिन कोई बड़ा भाई रोज आकर छोटो भाई को दो थप्पड़ मारेगा, रोज आकर उसको डांटेगा, तो छोटा भाई भी बेचारा कब तक बर्दाश्त करेगा। तो अगर आपको छोटे भाई का दिल जीतना है, तो छोटे भाई का दिल जीतना पड़ेगा। छोटे भाई का दिल जीतना है, तो छोटे भाई को प्यार करो, छोटे भाई के साथ चलो, तभी छोटा भाई आपका साथ देगा, मैं इस प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ।

माननीय अध्यक्षः अब श्री संजीव झा, माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है, वो हां कहें,

जो इसके विरोध में है, ना कहे,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हॉ पक्ष जीता संकल्प स्वीकार हुआ।

अब सदन की बैठक कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है और कल बजट पेश होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।